माननीय न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी, एच.एस. बेदी और एस. एस. सुधालकर के समक्ष

अनिल सभरवाल

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य।

1996 का सीडलयूपी नंबर 5851

21 मार्च, 1997

भारत का संविधान। 1950- अनुच्छेद 226 जी - जनहित याचिका - हरियाणा के शहरी एस्टेट में भूखंडों के विवेकाधीन कोटा आवंटन को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अदालत के ध्यान में लाकर जनता के मुद्दे का समर्थन किया है कि समाज के शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों ने विवेकाधीन कोटा के तहत किए गए आवंटन के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और यदि मनमाने तरीके से उन्हें आवंटित प्रमुख भूमि बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तब सरकारी खजाने को बहुत लाभ होगा और सभी पात्र व्यक्ति नीलामी के माध्यम से या आवंटन के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है कि जो लोग राजनीतिक सत्ता के तार खींचने में सक्षम हैं, वे संवैधानिक नैतिकता की उपेक्षा करके लाभ उठा सकते हैं। इसलिए, हमें प्रतिवादियों/आपत्तिकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई दम नहीं दिखता है कि रिट याचिका को आधार की कमी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 226- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 - धारा 15 (3) और 30 (1) - हरियाणा में भूखंडों के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री का 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा - मुख्यमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार आवंटन करने के लिए पूर्ण विवेक के साथ निहित नहीं है - हुडा को निर्देश देने की सरकार की शक्तियां असीमित या निरंकुश नहीं हैं और यह केवल कुशल के लिए दी जा सकती है।

अधिनियम के तहत प्रशासन - ऐसे आवंटन न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अदालत के ध्यान में लाकर जनता के मुद्दे का समर्थन किया है कि समाज के शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों ने विवेकाधीन कोटा के तहत किए गए आवंटन के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और यदि मनमाने तरीके से उन्हें आवंटित प्रमुख भूमि बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तब सरकारी खजाने को बहुत लाभ होगा और सभी पात्र व्यक्ति नीलामी के माध्यम से या आवंटन के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है कि जो लोग राजनीतिक सत्ता के तार खींचने में सक्षम हैं, वे संवैधानिक नैतिकता की उपेक्षा करके लाभ उठा सकते हैं। इसलिए, हमें प्रतिवादियों/आपत्तिकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई दम नहीं दिखता है कि रिट याचिका को आधार की कमी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुख्यमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार भूखंडों का एक विशेष प्रतिशत आवंटित करने का पूर्ण विवेक नहीं है। किसी वर्ग या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में भूखंडों को आरक्षित करने की नीति को किसी दिए गए मामले में अधिनियम के प्रयोजनों के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता है। सरकार के निर्देशों के तहत एक व्यक्ति को भूखंड का आवंटन किसी दिए गए मामले में भी उचित हो सकता है, लेकिन यह तर्क कि पूर्ण विवेक एक व्यक्ति में निहित हो सकता है, अधिनियम और संविधान की योजना के साथ पूरी तरह से असंगत है। इसी तरह, इस तर्क को भी नकारात्मक माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री को दिया गया विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा से मुक्त है, क्योंकि यह 'कानून के शासन' के सिद्धांत के विपरीत है जो भारतीय संविधान का मूल है। यह तर्क इसलिए भी अस्वीकार्य है क्योंकि हमारे देश में जनता के प्रतिनिधि चुनाव के समय जनता द्वारा जताए गए विश्वास के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत हुडा को भूखंडों को आरक्षित करने के लिए निर्देश देने के लिए सरकार की शक्तियों का उपयोग एक समूह के रूप में प्रतिष्ठित पेशेवरों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों आदि के पक्ष में किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा आरक्षण अधिनियम के मापदंडों, योजना और उद्देश्यों के भीतर हो। वास्तव में, हुडा द्वारा सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में भूखंड आरक्षित करने का नीतिगत निर्णय इसी श्रेणी में आता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पेशेवरों आदि के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन सरकार/हुडा द्वारा बनाई गई नीति का विज्ञापन जारी करने के बाद ही किया जा सकता है और आवंटन न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना होगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हमने पाया है कि अधिनियम के तहत, प्रतिवादियों को पूर्ण और बेलगाम विवेक प्रदान नहीं किया जा सकता है, अदालत संपत्ति को बहाल करने के अपने कर्तव्य में विफल रहेगी क्योंकि यह जनता है जो राज्य में निहित संपत्ति का वास्तविक मालिक है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एसआर दास के मामले में दिए गए फैसले के आलोक में उन आवंटनों को परेशान करना उचित नहीं होगा, जिन्होंने वैधता का रंग हासिल कर लिया है।

न्यायपालिका के सदस्यों और लोक सेवा आयोगों तथा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

जैसी एजेंसियों को भूखंडों के आवंटन के लिए विवेकाधीन कोटा से इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचने की संभावना है।

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14 और 22 और भूखंडों के आवंटन के लिए मानदंड - प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोग - प्रतिष्ठित और जरूरतमंद कौन है, इस सवाल को निर्धारित करने के लिए गाइड लाइनों का अभाव अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। 1989 को अवैध घोषित किया गया और सीमाओं और निर्देशों के अधीन पूर्वव्यापी रूप से रद्द कर दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूखंड के आवंटन के उद्देश्य से कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित और जरूरतमंद है या नहीं, यह सवाल मुख्यमंत्री की मर्जी पर निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रतिष्ठित और जरूरतमंद कौन हैं, इस प्रश्न के निर्धारण के लिए किसी भी दिशा-निर्देश के अभाव में, यह मुख्यमंत्री की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि वह उन्हें एक प्रतिष्ठित और जरूरतमंद व्यक्ति मानते हुए एक भूखंड आवंटित करें। मानदंड यह नहीं कहता है कि आवेदक/भावी आवंटी ने राष्ट्रीय कारण या राज्य के हित की सेवा करके खुद को प्रतिष्ठित किया होगा या उसने विज्ञान, कला, खेल, संगीत, पत्रकारिता, साहित्य या इसी तरह के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर विशिष्टता हासिल की होगी। इस बात का कोई संकेत नहीं हैं कि मुख्यमंत्री यह कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई व्यक्ति जरूरतमंद है या नहीं, आय का मानदंड निर्धारित किया गया है। विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंडों के आवंटन की शक्ति के प्रयोग के लिए ऐसा कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया है। कोई नियम या विनियमन नहीं बनाया गया है और कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है जिसका पालन करके मुख्यमंत्री यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित और जरूरतमंद है। सब कुछ मुख्यमंत्री के निरंकुश विवेक पर छोड़ दिया गया है। इस तरह की बेलगाम और अनिर्देशित शक्ति प्रदान करना स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 / संविधान में सन्निहित समानता के सिद्धांत को दी गई व्यापक व्याख्या के खिलाफ है।

इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पारित किसी भी आदेश में विचलित और जरूरतमंद व्यक्तियों के मानदंड का कोई संदर्भ नहीं है। यह स्पष्ट रूप से 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' के मानदंडों की अस्पष्टता का संकेत है। अस्पष्ट और मनमाने मानदंडों का लाभ उठाते हुए, अधिकांश आवेदक जिन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित नहीं किया है, उन्हें बड़े या छोटे भूखंडों के रूप में बड़े पैमाने पर छूट प्रदान की गई है। कुछ मामलों में, एक परिवार के सदस्यों को दो या दो से अधिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन के कुछ लाभार्थियों के पास दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में महलनुमा घर हैं। उन्हें एक से दो कनाल के बड़े भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसलिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अनुबंध आर-II में शामिल मानदंड अस्पष्ट और मनमाना है। यदि मुख्यमंत्री को असीमित अनिर्देशित और बेलगाम विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है, तो वह इस बात पर विचार किए बिना भी भूखंड आवंटित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में प्रतिष्ठित और जरूरतमंद है या नहीं।

भारत का संविधान। 1950 - कला। 226-और' को 'विशिष्ट और जरूरतमंद' आवंटन के मानदंड में 'या' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है - 'और' संयुक्त 'या' अस्पष्ट है - व्याख्या।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि हम 'या' शब्द के स्थान पर 'या' शब्द को पढ़ते हैं और दिनांक 21.11.1990 के नोट में शामिल मानदंड एक तमाशा बन जाएगा। ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं जिन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी असाधारण नहीं किया है, लेकिन उन्हें अभी भी भूखंडों की आवश्यकता हो सकती है। यदि इन सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के आधार पर भूखंड आवंटित किए जाते हैं, तो शायद मुख्यमंत्री को सभी शहरी सम्पदा ओं में पूरी भूमि आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अन्यथा उसे अपनी पसंद के व्यक्तियों को चुनकर उन्हें दान प्रदान करना होगा। इस तरह से शक्ति का प्रयोग संविधान के साथ पूरी तरह से धोखा होगा। शब्द 'या', सामान्य रूप से अस्पष्ट और शब्द है। और' सामान्य रूप से नेत्रश्लेष्मला है। के लिए। व्याख्या का उद्देश्य, ये शब्द -हो सकते हैं। यदि शब्दों का शाब्दिक पठन अस्पष्ट या बेतुके परिणाम उत्पन्न करता है तो आपस में बदल दिया जाता है। हालांकि, इस तरह के पाठ्यक्रम को आसानी से नहीं अपनाया जा सकता है।

भारत का संविधान। 1950 - अनुच्छेद 226 - संभावित अति-निर्णय के सिद्धांत को उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है - केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा अधिकार क्षेत्र है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, संभावित अति-निर्णय के सिद्धांत को केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इसलिए, हमें इस बात का कोई आधार नहीं मिलता है कि विवेकाधीन कोटा के तहत प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा किए गए आवंटन अबाधित रहने चाहिए।

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि:-

1. अधिनियम की धारा 15 और धारा 30 के प्रावधान प्रमुख को बेलगाम और अनिर्देशित शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं।

   मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विवेकके अनुसार आवासीय भूखंडों का आवंटन करें और इसका उपयोग मुख्यमंत्री को ऐसी शक्तियां प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है;

2. मुख्यमंत्री द्वारा 21 नवंबर, 1990 के नोट के माध्यम से भूखंडों के आवंटन के लिए तैयार किए गए मानदंड अर्थात 'विशिष्ट और जरूरतमंद लोग' अस्पष्ट और मनमाना है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है;

3. 31 अक्टूबर, 1989 को या उसके बाद मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत किए गए आवासीय भूखंडों के आवंटन को अवैध घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। यह निम्नलिखित के अधीन होगा :-

i. विवेकाधीन कोटे के तहत किए गए आवंटन उन आवंटियों और उनके वास्तविक खरीदारों के मामले में अप्रभावित रहेंगे, जिन्होंने पहले ही निर्माण शुरू कर दिया है या जिन्होंने इस याचिका के नोटिस के प्रकाशन की तारीख यानी 6 जून से पहले हुडा द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार घरों और भवनों का निर्माण शुरू कर दिया है। 1996. हालांकि, हुडा अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे आवंटियों/हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा तीसरे पक्ष को निर्मित घरों / भवनों के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए सामान्य निर्देश जारी करेगा।

ii जिन व्यक्तियों को 2 से 6 मरला के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें केवल तभी भूखंडों को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी जब उनके परिवार के पास हरियाणा / चंडीगढ़ राज्य में घर नहीं है। तीसरे पक्ष के लिए अलगाव के खिलाफ शर्त उनके मामलों में भी लागू होगी।

iii उन आवंटियों के मामले जो सशस्त्र बलों/अर्ध-सैनिक बलों के सदस्य थे/हैं, जिन्होंने राष्ट्र के हित के लिए बलिदान दिया है या जिन्होंने सेवा के दौरान अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, साथ ही पुलिस बलों के सदस्य जिन्होंने पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों और देश में कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वे नागरिक जो देश में आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित हुए हैं। पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों और देश में अन्य जगहों की समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? कमेटी।

iv रक्षा कामकों/पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ नागरिक जिनके मामलों की समीक्षा सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा की जानी है, उन्हें समिति की सिफारिशों पर प्रति परिवार केवल एक भूखंड रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, वे पांच साल के लिए तीसरे पक्ष को भूखंड को अलग करने के हकदार नहीं होंगे।

v. आज से एक महीने के भीतर हरियाणा सरकार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करनी चाहिए जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य से हो, जो राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले या विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले सशस्त्र बलों/अर्ध-सैनिक बलों के सदस्यों को किए गए आवंटन के मामलों की जांच करेगी। उन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों की जांच उस समिति द्वारा की जाएगी जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और जो नागरिक आतंकवाद के कारण पीड़ित हुए हैं। सरकार और हुडा उन आवंटनों को नियमित करेंगे जिनके लिए समिति द्वारा सिफारिशें की गई हैं।

Vi यदि समिति/हुडा को पता चलता है कि किसी आवंटी ने हुडा को झूठी सूचना दी है, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में आवंटन आवश्यक रूप से रद्द कर दिया जाएगा और सरकार ऐसे आवेदक के अभियोजन के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

5. हरियाणा सरकार व्यक्तियों के विनिदष्ट वर्ग को भूखंडों के आवंटन के लिए नीति तैयार कर सकती है और ऐसी नीति को अधिसूचित कर सकती है। ऐसी नीति के तहत आवंटन उन सभी से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके किया जाना चाहिए जो एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं।

6. सरकार/हुडा पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रसार के माध्यम से दो समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन तत्काल जारी करेगा और पूरे देश में दो समाचार पत्रों का प्रसार होगा जिसमें यह दर्शाया गया है कि विवेकाधीन कोटे के तहत किए गए आवंटन को रद्द करने के कारण आवंटी उनके द्वारा जमा किए गए धन की वापसी के हकदार हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन करना। यदि हुडा आवेदन करने के दो महीने के भीतर राशि वापस करने में विफल रहता है तो उसे प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

7. ऊपर उल्लिखित अपवाद खंडों द्वारा कवर किए गए मामलों को पूरे रिकॉर्ड के साथ समिति को भेजा जाएगा और समिति की सिफारिश पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

8. हुडा द्वारा किए गए आवंटनों को रद्द करने के कारण जो भूखंड उपलब्ध होंगे, उनका निपटान मौजूदा नीति के अनुसार किया जाएगा।

9. सरकार अपने स्वयं के अधिकारियों और हुडा के अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

माननीय न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी,

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मैं मोटे तौर पर भाई सिंघवी, जे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं कि विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंडों के आवंटन की नीति न केवल अस्पष्ट है, बल्कि यह भी है कि इसका दुरुपयोग बाहरी कारणों से किया गया है और तदनुसार इसे रद्द करने की आवश्यकता है। मैं सिंघवी से सहमत हूं कि छोटे भूखंडों के आवंटियों को बख्शा जाना चाहिए। प्राथमिक कारक जो मुझे इस दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करता है वह यह है कि इस नीति को एस आर दास के मामले में इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और एक खंडपीठ द्वारा वैध पाया गया था।

इसके अलावा, यह तर्क देना असंभव होगा कि जिस व्यक्ति को 2, 4 या 6 मारिया प्लॉट आवंटित किया गया था, उसने लाभ के उद्देश्य से आवंटन हासिल किया होगा। वास्तव में, विशिष्ट और जरूरतमंद व्यक्तियों को आवंटन की नीति शायद ही इस श्रेणी के आवंटियों पर लागू की जा सकती है (जैसा कि उनके लिए किसी भी तरह से दिखावा या अपमानजनक लगने का कोई मतलब नहीं है) उनमें से कोई भी प्रतिष्ठित और जरूरतमंद दोनों के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेगा, जो आवंटन के लिए *एक अनिवार्य शर्त* है। इस प्रकार, उनके मामलों में एक कानूनी दृष्टिकोण के बजाय एक न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसलिए पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, सरकारी आवास के आवंटन की वैधता निर्धारित करने में लागू किए गए सिद्धांत ो को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, जहां आवंटियों द्वारा उस नीति के संदर्भ में अच्छे पैसे का भुगतान करके भूखंड खरीदे गए हैं, जिसे एसआर दास के मामले में बरकरार रखा गया था। यह सर्वविदित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 2261 के तहत परिकल्पित विवेकाधीन राहत को किसी विशेष स्थिति को पूरा करने के लिए ढाला जा सकता है। इसलिए मेरा विचार है कि पिछले कई वर्षों से जो कुछ हो रहा है, उसका खुलासा करना आवश्यक है, फिर भी 2 से 6 मरला भूखंडों के संबंध में किए गए आवंटन को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हालांकि, इस मामले का एक और पहलू है जिसके बारे में मेरे विद्वान भाई के साथ विचारों में भिन्नता है। आवंटनों को रद्द करते हुए, यह माना गया है कि रक्षा और पुलिस कर्मियों के पक्ष में एक अपवाद बनाने की आवश्यकता है, कि वे एक खतरनाक राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और उनके मामले में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक सेवानिवृत्त मुख्य सचिव को प्रतिष्ठित और जरूरतमंद व्यक्तियों के रूप में उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। मुझे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन मेरी राय है कि आवंटियों का एक अलग मामला नहीं बनाया जाना चाहिए और परिकल्पित समिति को 7 मरला और उससे अधिक के भूखंडों के सभी आवंटनों की वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे समाज के विभिन्न अन्य वर्ग चाहे वे न्यायिक अधिकारी, राजनेता, स्कूल शिक्षक या डॉक्टर हों और बहुत से अन्य लोग भी राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उनके मामले रक्षा कर्मियों के समान ही वास्तविक हो सकते हैं और आवंटन के मानदंडों में अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं।

इसके अलावा, समिति (इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए) में तीन सदस्य होने चाहिए - एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवक जो मुख्य सचिव के रैंक से कम नहीं

होना चाहिए।

हमने देखा है कि कुछ आवंटियों ने अपने आवेदनों में गलत या गलत विवरण देकर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया है ताकि पहचान से बचा जा सके और दोहरे या यहां तक कि कई आवंटन हासिल किए जा सकें। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक विकल्प रखा जाना चाहिए कि यदि वे स्वेच्छा से एक भूखंड को छोड़कर सभी को आत्मसमर्पण करते हैं, तो आज से दो महीने की अवधि के भीतर, एक भूखंड के आवंटन के लिए उनके मामलों पर उपर्युक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, और एक जांच से पता चलता है कि यह दोहरे या एकाधिक आवंटन का मामला है, नीति के विपरीत और झूठे हलफनामों के आधार पर, वे न केवल आवंटन के लिए विचार किए जाने के लिए खुद को अयोग्य घोषित करेंगे बल्कि उस आधार पर आपराधिक अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस न्यायालय के एक या दो मौजूदा न्यायाधीशों ने विवेकाधीन कोटे के तहत या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूखंड आवंटित किए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बताना बंद कर दिया। मेरे विचार से और बड़े सम्मान के साथ यह चूक बेंच और फैसले को गंभीर आलोचना के लिए खुला बनाती है। आत्मनिरीक्षण एक कठिन और अक्सर एक शर्मनाक अभ्यास है लेकिन एक ऐसा कार्य है जिसे फिर भी किया जाना चाहिए। दूसरों के नामों का खुलासा करते समय, मुझे इस बात का कोई उचित कारण नहीं दिखता है कि इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों अर्थात माननीय न्यायमूर्ति एमएस लिब्रहन, माननीय न्यायमूर्ति एनसी जैन और माननीय न्यायमूर्ति एम एल कौल, जिन्हें या तो स्वयं या उनके परिवारों के माध्यम से लाभार्थियों के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।

इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में। आवंटन हासिल करने वाले न्यायिक अधिकारियों ने आवंटन के लिए सीधे मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था और कुछ आवेदनों में ऐसी भाषा है जो दासता पर आधारित है। इस प्रथा को गंभीरता से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे न्यायाधीशों की स्थिति और स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है। अत, मेरा मत है कि भविष्य में यदि किसी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी को विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत भूखंड प्रदान करने के लिए आवेदन करना है तो उक्त आवेदन उच्च न्यायालय के माध्यम से किया जाना चाहिए और यदि आवेदक उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश है तो वह मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह भी सभी को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि किसी भी अन्य तरीके से किए गए किसी भी आवेदन को विचार से खारिज कर दिया जाएगा।

माननीय न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी

1. पचास वर्ष पहले संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया था। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों ने डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में मुलाकात की, दो साल से अधिक समय तक बहस की, दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधानों की जांच और विश्लेषण किया और दस्तावेज़ तैयार किया जिसे "संविधान" के रूप में जाना जाता है। भारत"। संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया और भारत, जो 15 अगस्त, 1947 को शाही शासन से मुक्त हुआ, संविधान के लागू होने के साथ 26.1.1950 को एक गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है:-

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता;

स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना।"

"समाजवादी" शब्द संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में पेश किया गया था। हालांकि संविधान के XXII भागों में से प्रत्येक का अपना महत्व है, आम आदमी आम तौर पर भाग III, IV और भाग से चिंतित है। IV-A, अंतिम संशोधन बयालीसवें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। संविधान के भाग-III में नागरिकों और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इसमें कई निषेधात्मक निषेधाज्ञाएं भी शामिल हैं। भाग-IV के प्रावधानों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं जो देश के शासन के लिए मौलिक हैं। राज्य समाज के कमजोर वर्गों और ग्रामीण आबादी की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाने के लिए बाध्य है। भाग IV-A में भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। केके मैथ्यू, जे. के शब्दों में (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एआईआर 1973 एससी 1461):-

"... संविधान की स्थापना में लोगों का उद्देश्य न्याय, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यप्रणाली संविधान के भाग III और IV में निर्धारित की गई है.....

जैसा कि मैं भाग III और IV के प्रावधानों को देखता हूं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करने का मूल उद्देश्य भाग IV में निर्धारित आदर्शों की अंतिम उपलब्धि है.....

क्या मैं यह कह सकता हूं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को महज रेत की रस्सी नहीं बनने दिया जाना चाहिए। यदि राज्य ऐसी परिस्थितियाँ बनाने में विफल रहता है जिसमें सभी लोग मौलिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकें, तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता कई लोगों की दया पर निर्भर हो जाएगी और फिर सभी स्वतंत्रताएँ लुप्त हो जाएँगी।"

भाग IV-ए को जोड़ना आज की आवश्यकता पर जोर देता है, अर्थात् प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के साथ-साथ साथी नागरिकों के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए क्योंकि जब तक हर कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, न्याय और समानता के आदर्श कभी हासिल नहीं किए जा सकते। . अनुच्छेद 51ए प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का आदेश देता है; उन महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया; भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए... हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए;... व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और

उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ता जाता है। भाग IV-A के रूप में जो शामिल किया गया है वह संविधान की प्रस्तावना, भाग III और भाग-IV में निहित है क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकार तभी सार्थक हो सकते हैं जब राज्य और अन्य नागरिक इन्हें लाने के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच वास्तविक समानता।

2. संविधान के निर्माताओं और भाग IV-ए को पेश करने के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त प्रावधानों को इस आशा के साथ लागू किया कि प्रत्येक नागरिक एक सजातीय समाज के निर्माण में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएगा जिसमें प्रत्येक भारतीय शामिल होगा। भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी बातों की चिंता किए बिना सम्मान के साथ जीने में सक्षम और राष्ट्र लगातार आगे बढ़ेगा और राष्ट्रों के समुदाय में अपना गौरवपूर्ण स्थान लेगा। हालाँकि, पिछले कुछ दशकों में जो कुछ हुआ है वह उन उम्मीदों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। समाज के पास 'है' और 'नहीं है' के बीच का अंतर, जो स्वतंत्रता-पूर्व भारत में भी मौजूद था, इतना बढ़ गया है कि इसे पाटना असंभव प्रतीत होता है। लोगों का एक नया पंथ अस्तित्व में आया है। इस श्रेणी से संबंधित लोगों ने एक नई मूल्य प्रणाली विकसित की है जो भारतीय समाज द्वारा सदियों से पोषित मूल्यों और आदर्शों के साथ पूरी तरह से असंगत है। उन्होंने राजनीतिक और राजनीतिक तौर पर सत्ता हथिया ली है और अपने हितों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक संस्थानों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। कोटा, लाइसेंस, परमिट आदि की प्रणाली का उपयोग और दुरुपयोग उन्होंने अपनी भौतिक संपदा बढ़ाने के लिए किया है। उनके कार्यों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में संदेह का माहौल पैदा कर दिया है। आम आदमी को लगने लगा है कि रास्ते में जो भी आए उसे हड़प लेने में विश्वास रखने वाले लोगों का यह नया पंथ अजेय है और कानून भी उसका सेवक बन जाएगा क्योंकि इस वर्ग के बहुत से लोग कानून के निर्माता और प्रशासक हैं। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज़ खोई नहीं है। राज्य का तीसरा अंग जिसका प्राथमिक कर्तव्य संविधान और कानून के प्रावधानों की व्याख्या करना और व्यक्तियों और राज्य के बीच और व्यक्तियों के बीच या व्यक्तियों के समूहों के बीच विवादों का निपटारा करना है, लोगों द्वारा मजबूर किया गया है और कानून की महिमा और संविधान के अधिकार को बनाए रखने के लिए कदम उठाने की परिस्थितियाँ। मुकदमेबाजी का नया रूप जिसे लोकप्रिय रूप से 'जनहित याचिका' या जिसे कुछ लोग 'सामाजिक कार्रवाई मुकदमेबाजी' कहते हैं, के रूप में जाना जाता है, जिसका जन्म 1981-82 में हुआ था जो अब न्याय प्रदान करने की प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है। यद्यपि जनहित याचिका/सामाजिक कार्रवाई याचिका की अवधारणा के दुरुपयोग के कुछ छिटपुट मामले सामने आए हैं, लेकिन आम तौर पर इस नई व्यवस्था का उपयोग न्यायालयों द्वारा गरीबों और वंचितों के लाभ के लिए किया गया है, जिससे काफी हद तक जनता को बचाया जा सके। संपत्ति और पर्यावरण के क्षेत्र में सार्वजनिक हित, न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देश पारिस्थितिकी के विनाश को बचाने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित आदेश खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाते हैं, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाते हैं, निर्देश देते हैं वन क्षेत्रों में खनन कार्यों को रोकना अंततः भावी पीढ़ियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें न्यायालयों ने सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और सार्वजनिक हित/राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है, वह है सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा विवेक का मनमाना उपयोग। सचिव, जेडीए बनाम दौलत मल जैन, जेटी 1996(8) एससी 387 में, शीर्ष अदालत के पास मंत्री और मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा उत्तरदाताओं को भूमि आवंटन की जांच करने का अवसर था। उस निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के संदर्भ में काफी प्रासंगिक हैं। इसलिए, उन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:-

"... मंत्री संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद सार्वजनिक पद पर बने रहते हैं और संविधान, कानून कार्यकारी नीति के तहत कार्य करते हैं। किए गए कार्य और किए गए कर्तव्य सार्वजनिक पद धारण करने के रूप में सार्वजनिक कार्य या कर्तव्य हैं। इसलिए, उन्हें इसके लिए कुछ जवाबदेही देनी होती है। किए गए कार्य या किए गए कर्तव्य। कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, नियुक्ति के आधार पर संविधान द्वारा सार्वजनिक पद के धारक या संबंधित प्राधिकारी को शक्ति प्रदान की जाती है। इसलिए, पद के धारक को दुरुपयोग करने का अवसर मिलता है या पद का दुरुपयोग। सार्वजनिक पद धारण करने वाले राजनेता को नियमों या प्राथमिकताओं की भावना के तहत उद्देश्य की भावना और दिशा की भावना के साथ सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नियम द्वारा शासित एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज में उद्देश्य वास्तविक होना चाहिए सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कानून। कार्यकारी सरकार को सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता, प्रगति और नैतिकता को बनाए रखने के लिए अपनी नीतियां बनानी चाहिए। सरकार के सभी कार्य सामूहिक या संयुक्त या व्यक्तिगत क्षमता में व्यक्तिगत व्यक्तियों के माध्यम से/द्वारा किए जाते हैं। इसलिए, उन्हें नैतिक रूप से अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए... मंत्री न केवल अपने कार्यों के लिए बल्कि उन नौकरशाहों के काम के लिए भी जिम्मेदार है जो उसके अधीन काम करते हैं या काम कर चुके हैं। जिस विभाग का वह प्रमुख है, उसके संबंध में राज्यपाल के नाम पर किए गए अपने सभी कार्यों के लिए वह निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है। यदि मंत्री, वास्तव में, अपने विभाग के सभी विस्तृत कामकाज के लिए जिम्मेदार है, तो स्पष्ट रूप से मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी को केवल नैतिक जिम्मेदारी की तुलना में व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करना चाहिए; क्योंकि कोई मंत्री संभवतः परिचित नहीं हो सकता; उनके विभाग के कामकाज में शामिल सभी विस्तृत निर्णय... तथाकथित सार्वजनिक नीति सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण या लोक सेवक को सौंपी गई शक्ति और विश्वास के दुरुपयोग का मुखौटा नहीं हो सकती है। दुरुपयोग का तात्पर्य कुछ अनुचित कार्य करना है। अनौचित्य का सार सार्वजनिक उद्देश्य को निजी उद्देश्य से बदलना है। जब कर्तव्यों के पालन में मांगी गई संतुष्टि पारस्परिक व्यक्तिगत लाभ के लिए होती है, तो दुरुपयोग को आमतौर पर भ्रष्टाचार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी सार्वजनिक पद के

धारक ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जब निजी संतुष्टि के लिए, सार्वजनिक हित से अलग, उसने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक मंत्री से मांगी जाने वाली सबसे प्राथमिक योग्यता ईमानदारी और अविनाशीता है। उसके पास न केवल ये योग्यताएं होनी चाहिए बल्कि उसके पास ये योग्यताएं दिखाई भी देनी चाहिए।"

3. सामान्य कारण: एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य, जेटी 1996(8) एससी 613 में, सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन मंत्री द्वारा पेट्रोल पंप/खुदरा दुकानों के आवंटन पर सवाल उठाते हुए जनहित में दायर एक याचिका पर विचार किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों ने केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंद्रह व्यक्तियों के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द कर दिया। ऐसा करते समय शीर्ष अदालत ने कहा:-

".... सरकार आज - कल्याणकारी राज्य में - नागरिकों को बड़ी संख्या में लाभ प्रदान करती है। यह भूखंडों, घरों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, खनिज पट्टों, अनुबंधों, कोटा और लाइसेंस आदि के आवंटन के रूप में धन वितरित करती है। सरकार विभिन्न रूपों में उदारताएं वितरित करती है। एक मंत्री, जो संबंधित विभाग का कार्यकारी प्रमुख होता है, इन लाभों और उदारताओं को वितरित करता है। वह लोगों द्वारा चुना जाता है और उस पद पर पदोन्नत किया जाता है जहां वह लोगों की ओर से एक ट्रस्ट रखता है। उसके पास है लोगों की संपत्ति का उचित और उचित तरीके से निपटान करना..."

4. हमने उपरोक्त चर्चा के साथ सरकार के विवेकाधीन कोटे के तहत हरियाणा की विभिन्न शहरी संपदाओं में भूखंडों के आवंटन को चुनौती देने वाली इस रिट याचिका पर विचार करना शुरू कर दिया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतिवादी संख्या 3 और संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, अन्य राजनीतिक हस्तियों, न्यायपालिका के सदस्यों, लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, हरियाणा सिविल के सदस्यों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भूमि हड़पना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, 'हुडा') की सेवाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों, प्रतिवादियों ने रिट याचिका दायर करने के उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है।

5. रिट याचिका में, जैसा कि मूल रूप से स्थापित किया गया था, याचिकाकर्ता अनिल सभरवाल ने हरियाणा राज्य को पक्षकार बनाया; हुडा; श्री भजन लाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा-सह-अध्यक्ष, हुडा और सचिव-सह-संपदा अधिकारी (विवेकाधीन कोटा), हुडा पार्टियों के रूप में। उन्होंने आवासीय भूखंडों के आवंटन के विवेकाधीन कोटा को रद्द करने के लिए एक रिट जारी करने और विवेकाधीन कोटा के तहत उत्तरदाताओं द्वारा किए गए सभी आवंटन और व्यवसाय व्यापारियों और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में किए गए आरक्षण को रद्द करने के लिए प्रार्थना की। आरक्षण नीति. जब रिट याचिका आरपी सेठी, जे. (जैसा कि वह तब थे) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष आई, तो न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"1996 के सीएम नंबर 8111 की अनुमति दी जाती है, जिससे याचिकाकर्ता को याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट मिलती है, 1995(2) आरएसजे 553 को संदर्भित करता है।

इस रिट याचिका को जनहित में याचिका के रूप में माना जाता है।

रिट याचिका के पैरा 6 और 13 में दिए गए कथनों का संदर्भ दिया गया है और बार में कहा गया है कि विवेकाधिकार की आड़ में राजनेताओं, नौकरशाहों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों/अधिकारियों को कई भूखंड आवंटित किए गए हैं। कोटा. यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक उदारता के वितरण में सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है।

22 मई 1996 के लिए प्रस्ताव की सूचना।

प्रतिवादियों को अगली तारीख से पहले इस न्यायालय को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें पिछले दस वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में विवेकाधीन कोटा से भूखंड आवंटित किए गए हैं।

उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे व्यक्तियों को इस याचिका को दाखिल करने और अगली तारीख तय करने के बारे में सूचित करें, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए नोटिस माना जाएगा और यदि वे चाहें तो आपत्तियां दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इस याचिका के बारे में याचिकाकर्ता के खर्च पर व्यापक प्रसार वाले किसी समाचार पत्र में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा।

हरियाणा राज्य में विवेकाधीन कोटा से बाहर के भूखंडों के ऐसे सभी आवंटियों को अगले आदेश तक, इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी तरीके से उक्त भूखंडों को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करने या स्थानांतरित करने से रोका जाता है।"

6. 22.5.1996 को, न्यायालय ने नोट किया कि 23 अप्रैल, 1996 को दिए गए निर्देशों का उत्तरदाताओं द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है और कहा कि रिट याचिका में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस तरह मामला इस पीठ के सामने रखा गया. 30.5.1996 को न्यायालय ने महसूस किया कि उन सभी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होगा जो न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए, हुडा को तीन समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन को चुनौती देने वाली रिट याचिका के लंबित होने के तथ्य की जानकारी दी जाए और यह भी सूचित किया जाए कि ऐसे व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जवाब/शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं। . उस आदेश के जवाब में हुडा की ओर से विभिन्न समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करवाए गए। इसके बाद, व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से लगभग 210 आपत्ति याचिकाएँ दायर की गई हैं।

7. पार्टियों की दलीलों से उत्पन्न होने वाले विवादास्पद मुद्दों की जांच करने के लिए और जिन पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है, विवेकाधीन कोटा के विकास के इतिहास, आवंटन की प्रक्रिया में किए गए संशोधनों का पता लगाना आवश्यक है। विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों और रिट याचिका में लगाए गए कुछ आरोप।

(i) विवेकाधीन कोटा/मुकदमेबाजी का विकास।

8. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत हुडा की स्थापना और गठन से पहले, शहरी संपदा विभाग में भूखंड विभिन्न संपदा अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आवंटित किए गए थे। राज्य सरकार। प्रारंभिक चरण में, आवंटन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर या ड्रा द्वारा किया जाता था। वर्ष 1971-72 में, सरकार ने अपने विवेक से आवंटन के लिए भूखंड का कुछ प्रतिशत आरक्षित करने का निर्णय लिया। जब भी नए क्षेत्र के लिए भूमि जारी की जाती थी, तो विभिन्न श्रेणियों के कुल भूखंडों का पांच प्रतिशत सरकार अपने विवेक से आवंटन के लिए आरक्षित करती थी। कुछ भूखंड सरकारी कर्मचारियों को आवंटन के लिए भी आरक्षित किये गये थे। जो भूखंड आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के कारण समर्पण या पुनःग्रहण के कारण उपलब्ध हो जाते थे, उन्हें भी सरकार अपने विवेक से आवंटित करती थी। बाद में उसी क्षेत्र में काटे गए अतिरिक्त भूखंडों में से, सरकार के विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन के लिए आरक्षण का फिर से सहारा लिया गया। यह नीति प्रारंभ में शहरी सम्पदा फ़रीदाबाद और पंचकुला में आवंटन करते समय लागू की गई थी। बाद में, इसे हरियाणा के सभी जिलों/शहरी संपदाओं तक विस्तारित किया गया। हुडा की स्थापना के बाद, सरकार द्वारा आवंटन के लिए भूखंडों के आरक्षण के मुद्दे पर 15.2.1978 को नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचार किया गया था। शासन के विवेक के अनुसार भूखण्डों का आवंटन जारी रखने के प्रस्ताव को मद क्रमांक 11/2019 द्वारा अनुमोदित किया गया। एफ-VI(ii). श्री बंसी लाई, श्री देवी लाल और श्री भजन लाल के नेतृत्व वाली क्रमिक सरकारों द्वारा बड़ी संख्या में भूखंड आवंटित किए गए थे।

9. हालाँकि, वर्ष 1987 में श्री देवीलाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 1.6.1986 से 20.6.1987 तक किए गए विभिन्न श्रेणियों के विवेकाधीन कोटा भूखंडों के आवंटन को रद्द करने का निर्णय लिया। सरकार के निर्देशों की अनुपालना में हुडा के मुख्य प्रशासक ने मेमो नं. एडीए(आर)-87/20500-14 दिनांक 29.6.1987 और उपरोक्त अवधि के दौरान विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के सभी आवंटन रद्द कर दिए। इस आदेश का असर 2972 आवंटियों पर पड़ा। उनमें से लगभग एक हजार ने 29.6.1987 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं। एसआर दास बनाम हरियाणा राज्य , (1988-1) 93 पीएलआर 430 में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर दिनांक 29.6.1987 के आदेश को रद्द कर दिया। वहीं, डिवीजन बेंच ने कुछ आवंटनों को बरकरार रखा और अन्य आवंटनों से निपटने के निर्देश दिए। हरियाणा राज्य और अन्य ने विशेष अनुमति याचिका संख्या 10062/1988 दायर की जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने 12.9.1989 को निपटारा कर दिया। उनके आधिपत्य ने स्पष्ट रूप से माना कि वे उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता या अन्यथा पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे थे और विशेष अनुमति याचिका का निर्णय एसआर दास के मामले के तथ्यों तक ही सीमित था। एक श्री एमएल तायल ने भी एसआर दास के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.1.1988 के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की। 1988 की उस विशेष अनुमति याचिका संख्या 5580 में, शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर नोटिस जारी किया कि क्या विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश पहले से किए गए आवंटन को प्रभावित करेंगे या संभावित रूप से लागू होंगे। इस न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस दीवान ने भी विवेकाधीन कोटा के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार पर सवाल उठाते हुए 1988 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5096 दायर की। उस याचिका को डिवीजन बेंच ने

स्वीकार कर लिया और एक बड़ी बेंच को भेज दिया। हालाँकि, उस याचिका पर सुनवाई होने से पहले, श्री देवीलाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 1.6.1986 और 20.6.1987 के बीच किए गए आवंटन रद्द करने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया।

10. सरकार द्वारा भूखंडों के आवंटन को रद्द करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता की अध्यक्षता में 25-6-1990 को आयोजित हुडा की 46वीं बैठक में विवेकाधीन कोटा से संबंधित मुद्दे की समीक्षा की गई। हुडा ने विवेकाधीन कोटेशन के तहत किसी भी सेक्टर/शहरी संपत्ति में सभी आकार के नए कटे हुए भूखंडों में से 5 प्रतिशत के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सभी पुन: प्रारंभ/सरेंडर किए गए भूखंडों, 15 प्रतिशत मूल्य का भुगतान न करने के कारण रद्द किए गए सभी भूखंडों और लॉटरी से बचे सभी बिना बिके भूखंडों को भी विवेकाधीन कोटा के तहत रखा गया था।

11. जून, 1990 में, विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था। 22.6.1990 को, तत्कालीन मुख्य सचिव ने विचार व्यक्त किया कि लीगल रिमेंबरेंसर की राय प्राप्त की जा सकती है कि क्या ऐसे आवंटन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक है। हालाँकि, 25.6.1990 को मुख्यमंत्री के सचिव ने मुख्यमंत्री की इच्छा से अवगत कराया कि उनके विवेक पर 5 प्रतिशत आवासीय भूखंड आवंटित करने की प्रथा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हुडा द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, मुख्यमंत्री के सचिव ने एक नोट तैयार किया जिसमें सुझाव दिया गया कि 25.6.1990 को आयोजित हुडा की बैठक की कार्यवाही के प्रसारण के तुरंत बाद, विवेकाधीन कोटा आवंटन की शक्ति प्रमुख के पास होगी मंत्री. उन्होंने यह भी कहा कि इस उद्देश्य के लिए कोई नीति या दिशानिर्देश तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और केवल एक चीज जो ध्यान में रखी जानी है वह यह है कि आवंटन चाहने वाले व्यक्ति के पास पूरे हरियाणा राज्य में कोई आवासीय भूखंड या घर नहीं हो सकता है। उसके स्वयं के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य (पत्नी/पति/आश्रित बच्चे) के नाम पर। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भूखण्डों के आवंटन के लिए निम्नलिखित नोट को मंजूरी दे दी:-

"इन भूखंडों को मुख्यमंत्री अपने विवेक से जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों को इस शर्त के साथ आवंटित करेंगे कि वे अपने नाम पर या अपने परिवार में से किसी एक के नाम पर न हों। पत्नी और आश्रित बच्चों सहित सदस्य, संबंधित शहरी संपत्ति में कोई अन्य घर या प्लॉट। शहरी संपत्ति, पंचकुला के मामले में, विवेकाधीन कोटा आवंटन से आवंटियों के पास चंडीगढ़ या मोहाली की स्थगित शहरी संपत्ति में कोई घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए। पंजाब राज्य में.

आवंटियों को पत्नी और आश्रित बच्चों सहित उनके परिवार के सदस्यों में से किसी एक के नाम पर किसी भी शहरी संपत्ति में विवेकाधीन कोटा के तहत पहले आवासीय भूखंड आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।"

12. मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 21.11.1990 को फाइल पर दर्ज किया गया। यह नोट मुख्य सचिव को भेज दिया गया. इसके बाद इसे हुडा को भेज दिया गया। उसी समय, सरकार/हुडा ने शपथ पत्र का मसौदा तैयार किया जिसे आवंटियों द्वारा दाखिल किया जाना आवश्यक था और सूचना पत्र का मसौदा तैयार किया गया जिसे हुडा द्वारा आवंटियों को भेजा जाना आवश्यक था।

13. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा दर्ज किए गए निर्णय को श्री ओम प्रकाश चौटाला और सहकारिता एवं नगर नियोजन मंत्री श्री धीरपाल सिंह की अध्यक्षता में हुडा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

14. जून, 1991 में श्री भजनलाल पुनः मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर, 1991 में प्रतिवादी संख्या 3 के आदेश पर निम्नलिखित आदेश दर्ज किया गया: -

"मैंने यह मामला देखा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, 25.6.1990 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर पिछली प्रथा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार शपथ पत्र मांगा जा सकता है।" इसके अलावा, जैसा कि मैंने निर्देश दिया है, तीन साल के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाए और सार्वजनिक पार्कों और हरित पट्टियों पर भूखंडों की नक्काशी पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।"

इन निर्देशों के अनुपालन में मुख्य प्रशासक, हुडा ने ज्ञापन संख्या एडीए (आर) -91/22819 दिनांक 29-10-1991 (अनुलग्नक आर 2) जारी किया और विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित भूखंडों के हस्तांतरण पर एक अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। संपदा अधिकारी द्वारा औपचारिक आवंटन पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष। यह प्रतिबंध उन भूखंडों पर भी लागू किया गया है, जिनका आवंटन निर्देश जारी होने से पहले हो चुका था।

(ii) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भूखंडों का आरक्षण।

14-8-1987 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में, हुडा ने विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भूखंडों के आरक्षण की एक नीति विकसित की। हुडा के समक्ष रखे गए प्रस्ताव का सार निम्नलिखित शब्दों में था।

"विभिन्न श्रेणियों के लिए आवासीय भूखंडों के आरक्षण के संबंध में नीति।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आवासीय भूखंडों के आरक्षण की नीति का पालन कर रहा है: -

1. सरकार. सभी आकार के भूखंडों में नौकरों को 5%।
2. रक्षा कार्मिक सभी आकारों में 20%।
3. एससी ईडब्ल्यूएस में 20%, 4 और 6 एम में 15%।
4. ईडब्ल्यूएस में बीसी 5%, 4 और 6 एम में 3%।
5. युद्ध विधवा/विकलांग सैनिक। ईडब्ल्यूएस में 5%, 4 और 6 एम में 3%।
6. विकलांग। ईडब्ल्यूएस में 1%, 4 और 6 एम में 1%।
7. स्वतंत्रता सेनानी. ईडब्ल्यूएस में 2%, 4 और 6 एम में 2%।

कम लागत वाली आवास योजना में एससी, बीसी, घुमंतू जनजातियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्रमशः 15%, 10%, 5% और 10% का आरक्षण मौजूद है।

विशिष्ट श्रेणियों के लिए उपरोक्त आरक्षण के अलावा, भूखंडों की कुल संख्या का 5% तथाकथित विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित किया जाता था। यह प्राधिकरण द्वारा 15.2.1978 को आयोजित अपनी छठी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार था। इस बैठक में 1972 यानी प्राधिकरण के गठन से पहले से चली आ रही प्राथमिकताओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार भूखंडों का एक निश्चित प्रतिशत विशेष रूप से सरकार द्वारा अपने विवेक से आवंटन के लिए आरक्षित किया जा रहा था। सामान्य प्रथा यह थी कि नए क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी में भूखंडों की कुल संख्या का 5% सरकार द्वारा अपने विवेक से आवंटन के लिए आरक्षित किया जाता था। पूर्ववर्ती शहरी संपदा विभाग में विवेकाधीन कोटा की प्रथा। 14.7.1971 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा फ़ाइल पर लिए गए निर्णय का अनुसरण करता है। जिसके अनुसार सेक्टर 21, फ़रीदाबाद में 15% भूखंड हरियाणा विधानसभा के सदस्यों और संसद सदस्यों के लिए आरक्षित थे और अन्य 5% भूखंड राज्य सरकार द्वारा कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे "राजनीतिक पीड़ित, प्रतिष्ठित कलाकारों" के लिए विवेकाधीन आवंटन के लिए आरक्षित थे। लेखक, पत्रकार और अन्य योग्य मामले"। ये विवेकाधीन कोटे के भूखंड मंत्री/मुख्यमंत्री के आदेश के तहत आवंटित किये गये थे। पुराने सेक्टरों में सरेंडर किए गए/फिर से शुरू किए गए/अआवंटित/नए सिरे से काटे गए सभी भूखंडों को बाद में 6.10.1981 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में विवेकाधीन कोटा में जोड़ा गया (अनुलग्नक)....."

हालाँकि, हुडा द्वारा लिया गया निर्णय निम्नलिखित शब्दों में था: -

"विभिन्न श्रेणियों के लिए आवासीय भूखंडों के आरक्षण के संबंध में नीति।

एजेंडे में शामिल प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी. सरकार के लिए आवासीय भूखंडों के आरक्षण अनुपात को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। नौकर और रक्षा कार्मिक. अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण यथावत रखा गया। हरियाणा सरकार/बोर्डों/निगमों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए सभी आकार के भूखंडों में 5% के मौजूदा आरक्षण को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। रक्षा कर्मियों के लिए आरक्षण अधिसूचित स्थानों पर सभी आकार के भूखंडों में 20% और अन्य स्थानों पर 10% होगा। आगे यह निर्णय लिया गया कि केवल हरियाणा अधिवासी रक्षा कार्मिक/पूर्व सैनिक ही आरक्षित श्रेणियों के भूखंडों के लिए पात्र होंगे।

विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आवासीय भूखण्डों का आरक्षण प्रथम आवंटन के समय ही उपलब्ध होगा। आरक्षित श्रेणियों के कोटे के अभ्यर्पित/रद्द/अआवंटित भूखंड सामान्य श्रेणी के भूखंडों को मिलेंगे।

विभिन्न श्रेणियों के भूखंडों के आवंटन में प्राथमिकताएं तय करने के लिए विस्तृत मानदंड तैयार कर अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखे जाएंगे।

सभी विद्यमान सेक्टरों में अभ्यर्पित/पुनः अस्वीकृत/अआवंटित/रद्द किये गये एवं नये बनाये गये भूखण्डों को खुली नीलामी में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आगे यह निर्णय लिया गया कि यदि मुख्य प्रशासक, हुडा को लगता है कि किसी विशेष चयनित/आकर्षक क्षेत्र में, भूखंडों की नीलामी में आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत मिलेगी, तो वह उस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।" इस स्तर पर, हम यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 ने अपने उत्तर के साथ अनुलग्नक आर 2 के रूप में जो रखा है वह एक एजेंडा आइटम के अलावा और कुछ नहीं है और हुडा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है।

(iii) याचिकाकर्ता का मामला।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वह फरीदाबाद के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर 28, फ़रीदाबाद के सदस्य हैं। वह सनातन धर्म सभा, फ़रीदाबाद के सदस्य भी हैं। उन्होंने जनहित में यह याचिका दायर की है जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए सत्ता के दुरुपयोग/दुरुपयोग, संविधान के उल्लंघन के आधार पर सभी आवासीय भूखंडों के आवंटन पर सवाल उठाए गए हैं। अधिनियम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विनियमन, 1979 (विनियम) के प्रावधान। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हुडा द्वारा पारित प्रस्ताव में कथित तौर पर निर्धारित 5% कोटा से कहीं अधिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रभावशाली व्यक्तियों को बड़ी संख्या में बड़े भूखंड आवंटित किए हैं जिनमें सार्वजनिक प्रतिनिधि, न्यायपालिका के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और अन्य शामिल हैं जो भूमि के भूखंडों को हड़पने के लिए हैं। 1986 के सीएम नंबर 16905 के साथ दायर अतिरिक्त हलफनामे दिनांक 26.8.1996 में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उच्च-अधिकारियों के साथ संबंध रखने वाले कई व्यक्तियों के परिवारों ने एक या एक से अधिक शहरी संपदा में एक से अधिक भूखंड हासिल किए हैं। मुनाफाखोरी के घोषित उद्देश्य के साथ। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ आवेदकों ने विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन को सुरक्षित करने के लिए हुडा के समक्ष झूठे हलफनामे दायर किए। दिनांक 31.7.1996 को एक अन्य हलफनामे के रूप में दायर प्रतिकृति में, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 ने जानबूझकर कई प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित भूखंडों और डिवीजन बेंच द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित जानकारी को छुपाया है। एसआर दास के मामले का उल्लंघन किया गया है। प्रतिकृति में एक और आरोप लगाया गया है कि लगातार मुख्यमंत्रियों ने अपनी पार्टी के लोगों और विधायकों को भूखंड आवंटित किए हैं और विवेकाधीन कोटे के भूखंड वर्ष 1993 में संसद सदस्यों को कांग्रेस के क्षेत्र में रखने के लिए आवंटित किए गए थे जब उनकी सरकार थी। केंद्र को 'अविश्वास प्रस्ताव' का सामना करना पड़ रहा था. यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अप्रैल, 1996 में भूखंडों का आवंटन किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ये आवंटन ऐसी कीमत पर किए गए हैं जो बाजार मूल्य से काफी कम है और आवंटी ऐसे आवंटन से भारी मुनाफा कमा सकेंगे। अनुलग्नक A1, A2, A2-A और A3 में, याचिकाकर्ता ने उन व्यक्तियों का विवरण दिया है जिन्हें विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड आवंटित किए गए हैं, भले ही उनके/उनके परिवार के सदस्यों के पास पहले से ही हरियाणा की शहरी संपदा में भूखंड हों; जिन व्यक्तियों ने इस आशय का झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया कि उनके या उनके परिवार के सदस्यों के पास अन्य संपत्तियों में विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित कोई भी भूखंड नहीं है और उन आवंटियों की सूची, जिन्हें चंडीगढ़ में घर मिले हैं और उन्हें पंचकुला में भूखंड आवंटित किए गए हैं।

(iv) प्रतिवादी संख्या 1 का मामला।

17. हरियाणा राज्य द्वारा श्री एससी चौधरी, विशेष सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से दायर अपने लिखित बयान में, प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता के रिट याचिका दायर करने के अधिकार को चुनौती दी है। तब यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के संबंध में स्पष्ट रूप से गलत बयान दिया है। इसमें विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन का एक संक्षिप्त इतिहास दिया गया है और अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए आवंटन किसी भी कानूनी त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं।

(v) उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 का मामला।

8.5.1996 को उनके द्वारा दायर लिखित बयान में, प्रतिवादी संख्या 2 और 4 ने कहा है कि भूखंडों का आवंटन वर्ष 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवीलाल के विवेक के तहत किया गया था, लेकिन उस समय कोई नीति नहीं थी। समय। जून, 1979 में श्री भजनलाल मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान, विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन 1979 से 1986 तक जारी रहा। इसके बाद, वह केंद्र सरकार में स्थानांतरित हो गए और श्री बंसी लाल मुख्यमंत्री बने। उनके शासनकाल में भी विवेकाधीन कोटा आवंटन जारी रहा। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने आवंटन रद्द करने के आदेश जारी होने, रिट याचिकाएं दायर करने और उच्च न्यायालय के फैसलों के साथ हुए घटनाक्रम का विवरण दिया है। जवाब के पैरा 7 में कहा गया है कि पिछले छह महीनों के दौरान कुल 4407 प्लॉटों में से लगभग 1745 प्लॉट विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित किए गए थे - लेकिन उनमें से ज्यादातर 2 कनाल से 14 मरला तक के प्लॉट हैं। केवल 13 प्लॉट 2 कनाल (1000 वर्ग गज) के हैं और 193 प्लॉट 1 कनाल (500 वर्ग गज) के हैं। उत्तरदाताओं ने यह भी कहा है कि आवंटन विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के उद्देश्य से निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया गया है। हरियाणा के विभिन्न शहरी संपदाओं में अक्टूबर से अब तक किए गए भूखंडों के आवंटन को दिखाने के लिए इस उत्तर के साथ विवरण अनुलग्नक आर 1 दायर किया गया है।

24.7.1996 को उनके द्वारा दायर एक विस्तृत उत्तर में, उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 ने, दिनांक 8.5.1996 के संक्षिप्त उत्तर में उनके द्वारा किए गए दावे को दोहराते हुए, आगे कहा कि आवंटन सख्ती से दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए थे। भूखंडों के आवंटन के लिए अनुबंध आर14 के तहत प्रक्रिया तैयार की गई और प्रक्रिया विकसित की गई, क्योंकि प्रत्येक आवेदक को एक हलफनामा दायर करना आवश्यक था कि उसके पास अपने, अपने पति या पत्नी और आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई भूखंड नहीं है। विशेष शहरी संपदा को विवेकाधीन कोटे से किसी भी शहरी संपदा में प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं ने कहा है कि अब सरकार ने विवेकाधीन कोटा खत्म करने का फैसला किया है। इस लिखित बयान के पैरा 7 में, उत्तरदाताओं ने कहा है कि कुल 4407 आवंटनों में से लगभग 842 भूखंड विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित किए गए हैं। पैरा 12 में, यह कहा गया है कि जून, 1991 और मार्च, 1996 के बीच, उपरोक्त अवधि के दौरान किए गए 30889 के कुल आवंटन में से विवेकाधीन कोटा के तहत केवल 4875 भूखंड आवंटित किए गए हैं। पैरा 12 की अंतिम पंक्ति में, यह कहा गया है कि विवेकाधीन कोटा के तहत 1842 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि कुल फ्लोटेशन लगभग 2662 है। राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद भूखंडों के आवंटन के आरोप का विरोध किया गया है। अनुलग्नक R.19 का संदर्भ देकर उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4। उन्होंने दलील दी है कि 19.3.1996 को आम चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के सामान्य निर्देश जारी होने के बाद, हुडा के सचिव ने राय दी थी कि आवंटन पत्र जारी करना उचित नहीं होगा। सचिव के इस नोट (दिनांक 20.3.1996) पर मुख्य प्रशासक ने राय दी कि जिन मामलों में चुनाव की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा विवेक का प्रयोग किया जा चुका है, आवंटन पत्र जारी करना केवल एक प्रशासनिक कार्य था और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर ने एक नोट दर्ज किया कि मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव और हुडा के मुख्य प्रशासक की बैठक में निर्णय लिया गया कि लीगल रिमेम्बरेंसर, हरियाणा की सलाह ली जा सकती है। अपनी ओर से, कानूनी स्मरणकर्ता ने राय दी कि मुख्य प्रशासक द्वारा व्यक्त किए गए विचार सही थे। यह राय लीगल रिमेम्बरेंसर ने 21.3.1996 को व्यक्त की थी।

19. (vi) प्रतिवादी क्रमांक 3 का उत्तर।

हलफनामे के माध्यम से अपने अलग जवाब में, श्री भजन लाल ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कथित तौर पर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बनाई गई नीति का उल्लेख किया है और दलील दी है कि उन्होंने नीति में और अधिक बदलाव किए हैं, इसे और अधिक सख्त बनाया है और कुछ दिशा-निर्देश पारित करके विवेक के उपयोग को प्रतिबंधित किया है, जिसमें लाभार्थियों से हलफनामा मांगना शामिल है। . साथ ही उन्होंने सार्वजनिक पार्कों और ग्रीन बेल्ट से प्लॉट काटने पर भी रोक लगा दी है. विवेकाधीन कोटे के तहत आवंटित भूखंड के हस्तांतरण पर भी तीन साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिवादी नंबर 3 ने आगे दलील दी है कि उसे विवेकाधीन कोटा से आवंटन करने की खुली छूट नहीं है और आवंटन की नीति निष्पक्ष और उचित है। श्री भजन लाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन की शक्ति का उपयोग जनहित में और उस उद्देश्य के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के भीतर किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि संसद सदस्य एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वह विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड के आवंटन के लिए अयोग्य नहीं हैं।

20. (vii) आपत्तिकर्ताओं का मामला।

जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, 210 से अधिक आपत्ति याचिकाएं उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गई हैं जिन्हें भूखंड आवंटित किए गए थे/जिन्होंने मूल आवंटियों से हस्तांतरण के माध्यम से लिया है। मोटे तौर पर ये आपत्तियाँ हैं:-

(ए) उन्हें इस तथ्य के मद्देनजर मुख्यमंत्री के आदेश के तहत भूखंड आवंटित किए गए हैं कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के पास हरियाणा की किसी भी शहरी संपत्ति में कोई जमीन नहीं है।

(बी) वे प्रामाणिक खरीदार हैं।

(सी) उन्होंने हुडा से अपनी योजनाओं की मंजूरी हासिल करने के बाद भूखंडों पर निर्माण किया है।

(डी) वे सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के करीब होने पर विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड मिले हैं।

(ई) वे सेवानिवृत्त सेना कर्मी हैं और उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा की है और अपनी नौकरी की प्रकृति के कारण किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं हो सके।

(एफ) याचिकाकर्ता के पास विवेकाधीन कोटा के तहत किए गए आवंटन को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

21. प्रतिवादियों और आपत्तिकर्ताओं के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती दी कि उसे विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन से संबंधित विवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने परेशान करने के परोक्ष उद्देश्य से यह याचिका दायर की है। वे लोग जो किसी तरह विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंड प्राप्त कर सकते थे और जो अन्यथा लंबी अवधि की सेवा के बाद भी आश्रय के बिना रह जाते। विद्वान वकील ने भ्रष्टाचार निरोधक और समाज कल्याण संगठन बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1996-1)112 पीएलआर 53 में एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने रिट याचिका की स्थिरता पर उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों और एक नागरिक होने के नाते उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत के और हरियाणा राज्य के निवासी को विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग की आड़ में मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने को उजागर किया है, जो 'धनवान' श्रेणी के हैं और जो बड़े भूखंडों के आवंटन के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने में सक्षम हैं। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जिस तरह से संसद के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, अधीनस्थ और उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के सदस्य और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य गुड़गांव, फ़रीदाबाद, पंचकुला के शहरी संपदा के विभिन्न क्षेत्रों में प्राइम भूमि के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क किया और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भूखंडों के आवंटन का निर्देश दिया, वह मुख्यमंत्री के साथ-साथ आवेदकों द्वारा जनता के विश्वास का पूर्ण उल्लंघन दर्शाता है और उच्च सरकारी पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और दुरूपयोग से रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है।

23. हमने इस मुद्दे पर सोच-समझकर विचार किया है और हमारी राय में, याचिकाकर्ता को स्थिति की कमी के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

24. लोकस स्टैंडी से संबंधित मुद्दे पर समय-समय पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। पुराना नियम यह था कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जो राज्य या उसकी एजेंसियों की कार्रवाई से व्यथित है। हालाँकि, इस नियम ने धीरे-धीरे सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा विकसित नए तंत्र को रास्ता दिया है जो विशेष व्यक्तियों के बजाय आम तौर पर जनता को प्रभावित करते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य , एआईआर 1982 एससी 149 में, सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की 'स्थिति' के मुद्दे पर कानूनी स्थिति की समीक्षा की। भगवती, जे. ने न्यायालय के बहुमत के लिए बोलते हुए कहा:-

".....लोकस स्टैंडी के संबंध में पारंपरिक नियम यह है कि न्यायिक निवारण केवल उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जिसे अपने कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित के उल्लंघन के कारण कानूनी चोट लगी है। राज्य या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का या जिसे ऐसी किसी कार्रवाई से उसके कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित के खतरे के उल्लंघन के कारण कानूनी चोट लगने की संभावना है। न्यायिक निवारण के अधिकार का आधार संपत्ति को व्यक्तिगत चोट है , ऐसे निवारण की मांग करने वाले व्यक्ति के कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित के उल्लंघन, वास्तविक या धमकी से उत्पन्न शरीर, दिमाग या प्रतिष्ठा। यह प्राचीन काल का एक नियम है और यह उस युग के दौरान उत्पन्न हुआ जब निजी कानून कानूनी परिदृश्य पर हावी था और सार्वजनिक कानून का अभी तक जन्म नहीं हुआ था। इस नियम के तहत, न्यायालय इस सवाल से चिंतित था कि क्या आवेदक एक पीड़ित व्यक्ति था। इस नियम के अनुसार, यह केवल एक व्यक्ति था जिसे वास्तविक या धमकी के कारण विशिष्ट कानूनी चोट लगी थी उनके कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित का उल्लंघन किया गया है, जो सार्वजनिक रूप से उत्साही व्यक्ति द्वारा उनके मुद्दे का समर्थन करते हुए और उनके लिए

राहत की मांग करते हुए दायर की जाने वाली नियमित रिट याचिका के लिए कार्रवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे व्यक्तिगत अभिनय प्रोटोनो पब्लिको द्वारा संबोधित पत्र पर भी तत्परता से प्रतिक्रिया देगा..... एक और बिंदु जिस पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां कोई बाहरी सार्वजनिक चोट नहीं है राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य या चूक से, लेकिन ऐसे कार्य या चूक से किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के समूह को विशिष्ट कानूनी चोट भी पहुंचती है। ऐसे मामले में, पर्याप्त हित रखने वाला जनता का कोई सदस्य निश्चित रूप से ऐसे कार्य या चूक की वैधता को चुनौती देने वाली कार्रवाई कर सकता है....."

जनता दल बनाम एचएस चौधरी, एआईआर 1993 एससी 893 में , उनके आधिपत्य ने निम्नलिखित शब्दों के साथ 'जनहित याचिका' अभिव्यक्ति को अर्थ दिया: -

"....अभिव्यक्ति 'मुकदमेबाजी' का अर्थ है एक कानूनी कार्रवाई जिसमें सभी कार्यवाहियां शामिल हैं, जो किसी अधिकार को लागू करने या उपाय खोजने के उद्देश्य से कानून की अदालत में शुरू की गई है। इसलिए, शाब्दिक रूप से अभिव्यक्ति 'पीआईएल' का अर्थ है शुरू की गई कानूनी कार्रवाई सार्वजनिक हित या सामान्य हित के प्रवर्तन के लिए कानून की अदालत में जनता या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित या कुछ हित होता है जिससे उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। अभिव्यक्ति 'पीआईएल' की व्याख्या करने वाले कई निर्णय हैं आधुनिक समाज में वर्तमान संदर्भ में इसके व्यापक अर्थ में, जिनमें से कुछ का हम इस निर्णय के उचित भाग में उल्लेख करेंगे।"

चैतन्य कुमार बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य , एआईआर 1986 एससी 825 में, शीर्ष अदालत ने तीसरे पक्ष के कहने पर एक रिट याचिका पर विचार करने की मंजूरी दे दी, जिसमें बोतल अरक के अनुबंध को मंजूरी देने को चुनौती दी गई थी और कहा गया था: -

"...यह सच है कि एक जनहित याचिका में, सार्वजनिक रूप से उत्साही नागरिक होने का दावा करने वालों को दूसरों के चरित्र को धूमिल करने वाले जंगली और लापरवाह आरोपों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही, न्यायालय अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है और खुद को सार्वजनिक रूप से उजागर हुई शरारती कार्यकारी कार्रवाइयों को बनाए रखने के लिए राजी करें। जब मनमानी और विकृति बड़े पैमाने पर होती है और स्पष्ट रूप से सामने आती है, तो न्यायालय अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है और अपने रिट से इनकार नहीं कर सकता है। सार्वजनिक हित की उन्नति और सार्वजनिक शरारत से बचना है सर्वोपरि विचार। हमेशा की तरह, न्यायालय हितों के संतुलन से चिंतित है। जहां बोतल अरक को अनुबंध के अनुदान को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका में, यह स्थापित किया गया था कि कार्यकारी कार्रवाई मनमानी थी, उच्च न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं था इस तथ्य के बावजूद कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पक्षपात का आरोप झूठा पाया गया था, अनुबंध को रद्द करना।"

25. इस फैसले पर कई अन्य उदाहरणों का बोझ डाले बिना, हम इस न्यायालय के दो हालिया फैसलों का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसमें आरपी सेठी, जे. की अध्यक्षता वाली दो डिवीजन बेंचों ने जनहित याचिका पर विचार करने के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। वकीलों की पहल में श्री आर.एस. बैंस, अधिवक्ता और अन्य के माध्यम से। बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1995) 2 आईएलआर 279 और ईश्वर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य , (1995-2)110 पीएलआर 613, निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं: -

"लोकस स्टैंडी का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होगा और न्यायालय जनहित में मुकदमेबाजी की अनुमति देगा यदि यह पाया जाता है: -

(i) यह कि विवादित कार्रवाई भारत के संविधान के भाग III में निहित किसी भी अधिकार का उल्लंघन है और इसके प्रवर्तन के लिए राहत मांगी गई है।

(ii) जिस कार्रवाई की शिकायत की गई है वह स्पष्ट रूप से अवैध या दुर्भावनापूर्ण है और ऐसे व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करती है जो गरीबी, अक्षमता या अज्ञानता के कारण अपने हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं।

(iii) वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या संवैधानिक कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए सार्वजनिक हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा था।

(iv) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हस्तक्षेप करने वाला एक व्यस्त निकाय नहीं है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध या शिकायत को सही ठहराने के लिए गलत इरादे से संपर्क नहीं किया है।

(v) कि जनहित याचिका की प्रक्रिया का राजनेताओं, अन्य व्यस्त निकायों द्वारा राजनीतिक या असंबंधित उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे मुकदमे में राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक चूक सार्वजनिक रूप से उचित नहीं है।

(vi) जनहित में शुरू की गई मुकदमेबाजी ऐसी थी कि यदि उसका समाधान नहीं किया गया या रोका नहीं गया तो न्यायपालिका और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास कमजोर हो जाएगा।

(vii) कि राज्य की कार्रवाई को कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश की जा रही थी और इसे तकनीकी आधार पर उछालने का इरादा था।

(viii) जनहित याचिका या तो किसी पत्र या अन्य जानकारी प्राप्त होने पर शुरू की जा सकती है, लेकिन इस संतुष्टि पर कि न्यायालय के समक्ष रखी गई जानकारी ऐसी प्रकृति की थी जिसकी जांच की आवश्यकता थी।

(ix) कि न्यायालय में आने वाला व्यक्ति साफ हाथ, साफ दिल और साफ उद्देश्यों के साथ आया है।

(x) जनहित में कोई भी कार्रवाई करने से पहले न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उसके मंच का दुरुपयोग किसी बेईमान वादी, राजनेता, व्यस्त निकाय या व्यक्तियों या समूहों द्वारा अपनी व्यक्तिगत शिकायत को सही ठहराने के लिए या गलत उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग का सहारा लेना या जनहित से परे विचार करना।"

उल्लेखनीय है कि पहले मामले में पंजाब राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में निजी उत्तरदाताओं के नामांकन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन के मानदंड अवैध, मनमाने और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थे। संविधान का. याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र को चुनौती को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं को व्यस्त निकाय या हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदु अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के हैं और कार्रवाई की जानी है। असंवैधानिक और अवैध नीति/निर्देश/दिशानिर्देशों के तहत नामांकन करने के सरकार के अधिकार के संबंध में उत्तरदाताओं को इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की कसौटी पर परखा जाना आवश्यक है और इसलिए, याचिकाकर्ता गैर-नहीं हो सकते। इस आधार पर कि वे राज्य सरकार द्वारा किए गए नामांकन को चुनौती देने के लिए खड़े नहीं थे। 26. दूसरे मामले में, याचिकाकर्ता ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य , 1992(3) एससीसी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में गांव नौरंगपुर जिला गुड़गांव में पत्थर तोड़ने के व्यवसाय को बंद करने की मांग की थी। 356. उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के न्यायालय में जाने के अधिकार पर सवाल उठाया। आपत्ति को खारिज करते हुए, न्यायालय ने माना कि जिस कार्रवाई की शिकायत की गई है वह सार्वजनिक हित से संबंधित है, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन पर असर पड़ रहा है, जहां स्टोन-क्रशर्स स्थित हैं और क्योंकि आधिकारिक प्रतिवादी कानून के तहत उन पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं। क़ानून, उसके तहत बनाए गए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर याचिका सुनवाई योग्य थी।

27. हम सम्मानपूर्वक यहां ऊपर उल्लिखित दो डिवीजन बेंच के फैसलों से सहमत हैं। भ्रष्टाचार विरोधी और समाज कल्याण संगठन बनाम पंजाब राज्य , (सुप्रा) के फैसले में एक प्रस्ताव दिया गया है जो दो अन्य डिवीजन बेंच के फैसलों में निर्धारित कानून के प्रस्ताव के विपरीत है। उस मामले में, न्यायालय ने पाया कि याचिका एक परोक्ष उद्देश्य से दायर की गई थी और याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों के प्रति अपनी व्यक्तिगत शिकायत को संतुष्ट करना चाहता था जिन्हें अनुबंध दिया गया था। वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने न तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाया है और न ही यह दलील दी है कि उन्होंने इस याचिका को दायर करके व्यक्तिगत हिसाब-किताब तय करने की कोशिश की है या व्यक्तिगत लाभ लेने की कोशिश की है, जिन्हें दलीलों के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। और हुडा द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर करके अदालत के ध्यान में लाकर जनता के हित की वकालत की है कि समाज के शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों ने जनता को हड़प लिया है। विवेकाधीन कोटा के तहत किए गए आवंटन के आधार पर संपत्ति और उन्हें मनमाने तरीके से आवंटित की गई प्रमुख भूमि को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो सरकारी खजाने को बहुत फायदा होगा और सभी पात्र व्यक्ति भाग ले सकेंगे नीलामी के माध्यम से या आवंटन के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया में। इसके अलावा, याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि जो लोग राजनीतिक सत्ता की डोर खींचने में सक्षम हैं, वे संवैधानिक नैतिकता की उपेक्षा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, हम उत्तरदाताओं/आपत्तिकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि रिट याचिका को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

28. विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए बनाई गई तथाकथित नीति और उस नीति के अनुसार किए गए आवंटन को दी गई चुनौती की जांच के लिए रास्ते अब स्पष्ट हैं। याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया पहला और सबसे

महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उत्तरदाताओं के पास एचयूडी ए के निपटान में रखे गए भूखंडों को आवंटित करते समय विवेकाधीन कोटा तय करने का अधिकार नहीं था। याचिकाकर्ता और श्री आईके मेहता के वकील ने सीखा हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जित संपत्ति का विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन की आड़ में कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। चुनौती के इस आधार का एक और पहलू यह है कि विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए बनाए गए तथाकथित दिशानिर्देश अस्पष्ट और मनमाने हैं और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं।संविधान इसलिए क्योंकि यह मुख्यमंत्री को अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भूखंड आवंटित करने का बेलगाम और अनियंत्रित विवेक देता है। श्री एच.एस.हुड्डा, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा; श्री एमएल सरीन और श्री एचएल सिब्बल ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 15 सरकार को भूमि के निपटान के लिए हुडा को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है और इसलिए, प्रमुख के विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आरक्षण में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए कुल फ़्लोटेशन का 5% की सीमा तक मंत्री। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदाधिकारी को दिए गए विवेक को असंवैधानिक नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनसे इस विवेक का उपयोग निष्पक्ष और प्रामाणिक तरीके से और सार्वजनिक हित में करने की अपेक्षा की जाती है। विद्वान वकील ने एसआर दास के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों पर बहुत भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका की अस्वीकृति को वैधता का निर्णायक माना जाना चाहिए। आवासीय भूखंड आवंटित करने की मुख्यमंत्री की विवेकाधीन शक्ति। उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक हित के तत्व को मुख्यमंत्री को विवेकाधिकार प्रदान करने में निहित माना जाना चाहिए और इसलिए, 5% कोटा के नुस्खे को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए। श्री हुड्डा ने इस तथ्य पर जोर दिया कि विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटियों से ली जाने वाली कीमत क्षेत्र के अन्य आवंटियों से ली जाने वाली कीमत से कम नहीं है और इसलिए, मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। घृणित माना जाता है। श्री सरीन ने तर्क दिया कि 21.11.1990 को मुख्यमंत्री द्वारा दर्ज किए गए नोट में बताए गए मानदंड मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और तीन की समाप्ति से पहले स्वामित्व के हस्तांतरण के खिलाफ अनुबंध आर12 के तहत लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ एक पूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को, जिसे या जिसके परिवार के किसी सदस्य को उस कोटा के तहत प्लॉट आवंटित किया गया है, विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड के आवंटन पर लगाए गए प्रतिबंध के साथ वर्षों में, विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन की शक्ति के दुरुपयोग की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया गया है और मानदंड नहीं हो सकते हैं। इसे अनिर्देशित या अनियमित या मनमाना कहा जाता है। श्री सरीन ने तर्क दिया कि विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति प्रामाणिक है और एक बार उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखे जाने के बाद उस नीति को असंवैधानिक घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर, श्री एचएल सिब्बल ने तर्क दिया कि विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन की नीति तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 14.7.1971 को लिए गए निर्णय से प्रवाहित होती है, जिसके अनुसार विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों को कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटित किया जा सकता है। , जैसे राजनीतिक पीड़ित, प्रख्यात कलाकार, लेखक, पत्रकार और अन्य योग्य व्यक्ति। श्री सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि इस नीतिगत निर्णय को हुडा ने 14.8.1987 को हुई अपनी बैठक में सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जाति आदि के पक्ष में भूखंडों के कुछ अन्य आरक्षणों के साथ मंजूरी दे दी थी और यह नीति मनमानी के आरोप का पूर्ण उत्तर है। . श्री सिब्बल ने अनुबंध आर14 पर भी भरोसा किया, जिसमें हरियाणा की शहरी संपदा में विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शामिल है और तर्क दिया कि विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध और भूखंड के हस्तांतरण के खिलाफ लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध इस प्रकार लागू होता है। विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित भूखंडों के दुरुपयोग के खिलाफ एक लाभकारी जांच। श्री सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि प्रत्येक नागरिक भोजन, कपड़ा और आश्रय जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का हकदार है और राज्य का दायित्व है कि वह राज्य सहायता के सभी निवासियों को भूमि प्रदान करे, इसलिए, विवेकाधीन के तहत भूखंडों का आवंटन किया जाता है। कोटा असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त नहीं है। श्री सिब्बल के इस तर्क का आपत्तिकर्ताओं की ओर से उपस्थित कुछ विद्वान अधिवक्ताओं ने समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए कि पिछले कुछ दशकों के दौरान सामाजिक मूल्यों में भारी बदलाव आया है और युवा पीढ़ी के बीच माता-पिता से अलग रहने की प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि अगर बच्चों को शादी के बाद अलग आवास की आवश्यकता होती है, तो ऐसे युवाओं को विवेकाधीन कोटा के तहत जमीन उपलब्ध कराने का पर्याप्त औचित्य है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके परिवार के पास पहले से ही हरियाणा/चंडीगढ़ में घर है। श्री सरीन और श्री सिब्बल का एक और तर्क यह है कि मुख्यमंत्री के नोट में प्रयुक्त 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' अभिव्यक्ति में आने वाले शब्द 'और' को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और प्रतिष्ठित या जरूरतमंद लोगों को भूखंडों का आवंटन किया जाना चाहिए। अनुचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए कि पिछले कुछ दशकों के दौरान सामाजिक मूल्यों में भारी बदलाव आया है और युवा पीढ़ी के बीच माता-पिता से अलग रहने की प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि अगर बच्चों को शादी के बाद अलग आवास की आवश्यकता होती है, तो ऐसे युवाओं को विवेकाधीन कोटा के तहत जमीन उपलब्ध कराने का पर्याप्त औचित्य है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके परिवार के पास पहले से ही हरियाणा/चंडीगढ़ में घर है। श्री सरीन और श्री सिब्बल का एक और तर्क यह है कि मुख्यमंत्री के नोट में प्रयुक्त 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' अभिव्यक्ति में आने वाले शब्द 'और' को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और प्रतिष्ठित या जरूरतमंद लोगों को भूखंडों का आवंटन किया जाना चाहिए। अनुचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए कि पिछले कुछ दशकों के दौरान

सामाजिक मूल्यों में भारी बदलाव आया है और युवा पीढ़ी के बीच माता-पिता से अलग रहने की प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि अगर बच्चों को शादी के बाद अलग आवास की आवश्यकता होती है, तो ऐसे युवाओं को विवेकाधीन कोटा के तहत जमीन उपलब्ध कराने का पर्याप्त औचित्य है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके परिवार के पास पहले से ही हरियाणा/चंडीगढ़ में घर है। श्री सरीन और श्री सिब्बल का एक और तर्क यह है कि मुख्यमंत्री के नोट में प्रयुक्त 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' अभिव्यक्ति में आने वाले शब्द 'और' को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और प्रतिष्ठित या जरूरतमंद लोगों को भूखंडों का आवंटन किया जाना चाहिए। अनुचित नहीं कहा जा सकता।

29. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सोच-समझकर विचार किया है। हरियाणा विधानमंडल ने राज्य में शहरी विकास के लिए शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना और उसके सहायक मामलों के लिए अधिनियम बनाया। सरकार द्वारा जिस विधेयक के माध्यम से अधिनियम पेश किया गया था, उसके साथ विधानमंडल के समक्ष रखे गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, यह उल्लेख किया गया है कि पूरे हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण और शहरी क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जा रहा है। शहरी संपदा विभाग। जबकि शहरी क्षेत्रों की योजना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा की जाती है, भूमि का अधिग्रहण शहरी संपदा विभाग द्वारा किया जाता है और शहरी संपदा के विकास में कई एजेंसियों की भागीदारी समन्वय की समस्याओं को जन्म देती है। इससे शहरी संपदा का विकास धीमा हो गया है और भूखंड धारकों के साथ-साथ जनता भी असंतुष्ट है। इन कठिनाइयों को दूर करने और संपत्ति के त्वरित विकास को प्राप्त करने के लिए, एक शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना करना आवश्यक महसूस किया गया। अधिनियम की धारा 2 विभिन्न नियमों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है। धारा 3 हुडा की स्थापना और गठन का प्रावधान करती है। धारा 13 हुडा के उद्देश्यों और कार्यों को निर्दिष्ट करती है। धारा 15 में भूमि के निपटान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। धारा 30 सरकार द्वारा नियंत्रण की बात करती है। धारा 53 सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 54 हुडा को नियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 54 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 ने 1978 के विनियम बनाए हैं। इन विनियमों में से विनियम 3 निपटान के तरीके से संबंधित है जबकि विनियम 4 अस्थायी मूल्य/प्रीमियम के निर्धारण की बात करता है। विनियम 5 आवंटन द्वारा भूमि या भवन की बिक्री या पट्टे के मामले में प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इस निर्णय के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 13, 15, 30(1) और 1978 के विनियमों के विनियम 3 को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। इसे इस प्रकार पढ़ें: -

"एस. 13 - प्राधिकरण के उद्देश्य और कार्य: - प्राधिकरण का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में शामिल सभी या किसी भी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना होगा और उस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण के पास अधिग्रहण करने की शक्ति होगी भूमि और अन्य संपत्ति की खरीद, हस्तांतरण, विनिमय या उपहार, धारण, प्रबंधन, योजना, विकास और बंधक या अन्यथा निपटान का तरीका, स्वयं या अपनी ओर से किसी एजेंसी के माध्यम से निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन और अन्य संचालन करना, पानी की आपूर्ति, सीवरेज के निपटान, प्रदूषण के नियंत्रण और किसी भी अन्य सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में कार्यों को निष्पादित करना और आम तौर पर इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पूर्व अनुमोदन के साथ, या राज्य सरकार के निर्देश पर कुछ भी करना। .

xx xx xx xx S. 15 भूमि का निपटान: - (1) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश और उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण इसका निपटान कर सकता है -

(ए) राज्य सरकार द्वारा उसके द्वारा अर्जित की गई या उसे हस्तांतरित की गई कोई भी भूमि, उस पर कोई विकास कार्य किए बिना या किए बिना; या

(बी) ऐसी कोई भी भूमि, ऐसा विकास करने या करने के बाद, जैसा वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा वह विकास सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो प्राधिकरण को उपहार के माध्यम से भूमि का निपटान करने में सक्षम बनाता है, लेकिन इस शर्त के अधीन, इस अधिनियम में भूमि के निपटान के संदर्भ को किसी भी तरीके से उसके निपटान के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। , चाहे बिक्री, विनिमय या पट्टे के माध्यम से या किसी सुखभोग, अधिकार या विशेषाधिकार के सृजन के माध्यम से या अन्यथा।

(3) यहां पहले से निहित प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण अपनी किसी भी भूमि या भवन को नीलामी, आवंटन या अन्यथा ऐसे नियमों और शर्तों पर बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है, जो वह विनियमों द्वारा प्रदान कर सकता है।

(4) उप-धारा (1) के तहत किसी भी हस्तांतरण के लिए प्रतिफल राशि का भुगतान प्राधिकरण को उस तरीके से किया जाएगा जो विनियमन द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी भूमि या भवन या दोनों, जैसा भी मामला हो, तब तक प्राधिकरण का बना रहेगा जब तक कि संपूर्ण प्रतिफल राशि ब्याज और अन्य राशि के साथ न मिल जाए। यदि कोई हो, तो ऐसी भूमि या भवन या दोनों की बिक्री के कारण प्राधिकरण को देय राशि का भुगतान किया जाता है।

(6) जब तक विनियमों में प्रदान की गई शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक अंतरिती प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के अलावा भूमि या भवन में अपने अधिकारों को हस्तांतरित नहीं करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे नियमों और शर्तों के तहत दी जा सकती है।

xxxx xxxx

30. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण:- (1) प्राधिकरण इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करेगा।

xxxxxxxx विनियम 3- निपटान का तरीका:- अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश और अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन:-

(ए) प्राधिकरण अपनी किसी भी भूमि का निपटान विकसित या अविकसित रूप में कर सकता है;

(बी) प्राधिकरण की किसी भी भूमि या भवन का निपटान प्राधिकरण द्वारा बिक्री या पट्टे या विनिमय के माध्यम से या किसी सुखभोग अधिकार या विशेषाधिकार के निर्माण द्वारा या अन्यथा किया जा सकता है;

(सी) प्राधिकरण अपनी भूमि या भवन का निपटान बिक्री या पट्टे के माध्यम से या तो आवंटन या नीलामी द्वारा कर सकता है, जो खुली बोली या निविदाएं आमंत्रित करके हो सकता है।

xx xx xx xx"

30. इन प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि हुडा को शहरी क्षेत्र में शामिल सभी या किसी भी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हुडा को भूमि और अन्य संपत्ति के अधिग्रहण, विकास और निपटान का अधिकार है। धारा 15 हुडा को ऐसे व्यक्तियों को किसी भी विकास कार्य के साथ या उसके बिना, ऐसे तरीके से या ऐसे नियमों और शर्तों के तहत भूमि का निपटान करने का अधिकार देती है, जो विकास सुनिश्चित करने के लिए समीचीन प्रतीत होता है। हालाँकि, हुडा द्वारा भूमि का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अधीन है। धारा 15(2) उपहार के रूप में भूमि का निपटान करने के लिए हुडा पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 15 की उप-धारा (3) के तहत, हुडा को अपनी किसी भी भूमि या भवन को नीलामी या आवंटन या अन्यथा ऐसे नियमों और शर्तों पर बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा स्थानांतरित करने का अधिकार है, जैसा वह नियमों द्वारा प्रदान कर सकता है। उपधारा (6) हुडा की अनुमति के बिना भूमि या भवन में हस्तांतरित व्यक्ति द्वारा अधिकारों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 30 हुडा पर अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का कर्तव्य लगाती है। विनियम 3 जो भूमि या भवन के निपटान के तरीके की बात करता है, अधिनियम की धारा 15 के अनुरूप है।

31. आगे बढ़ने से पहले, हम एसआर दास के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिस पर उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 के लिए उपस्थित विद्वान वकील श्री सरीन ने बहुत जोर दिया है। अपने फैसले में, डिवीजन बेंच ने अधिनियम की धारा 3, 15, 30, 52, 53 और 54 के प्रावधानों और साइटों की बिक्री के नियमों का भी संदर्भ दिया, जो पहले बनाए गए थे और फिर देखे गए: -

"राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए धारा 53 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। उपरोक्त धारा के तहत साइटों की बिक्री के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। हालांकि, साइटों की बिक्री के नियम पहले बनाए गए थे, जो अभी भी अधिनियम के तहत भूखंडों की बिक्री पर लागू हैं। नियम 3 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि शहरी संपत्ति की उचित योजना और विकास के उद्देश्य से, व्यक्तियों के समूह या किसी पेशे का अभ्यास करने वाले या आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए साइटें आरक्षित की जा सकती हैं। कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय... (पैरा 16)।

xxxxxxxx उपरोक्त धाराओं, नियमों और विनियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास शहरी संपदा के विकास के उद्देश्य से हुडा को भूखंडों के आरक्षण सहित कोई भी निर्देश देने की शक्तियां हैं और हुडा ऐसा करने के लिए बाध्य है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश। यदि हुडा अपने किसी भी कर्तव्य को निभाने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है तो राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इस प्रकार, राज्य सरकार में निहित शक्तियाँ असीमित हैं। यदि ऐसी शक्तियों के अनुसरण में, इसने अपने विवेक से आवंटन के लिए भूखंडों का एक छोटा प्रतिशत आरक्षित किया है, तो आरक्षण को बुरा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विवेकाधीन कोटा का आरक्षण राज्य सरकार को विधायिका द्वारा प्रदत्त शक्तियों के लिए उचित रूप से प्रासंगिक है। . इसे डी स्मिथ की ज्यूडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, चौथे संस्करण में पृष्ठ 95 पर इस प्रकार देखा गया है:-

'हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह सिद्धांत दिया है कि 'विधानमंडल ने जिन चीज़ों को अधिकृत किया है, उन्हें जो कुछ भी उचित रूप से प्रासंगिक माना जा सकता है, या उसके परिणामस्वरूप, न्यायिक निर्माण द्वारा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए (जब तक कि स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो)। अधिकारातीत'। यह सिद्धांत सभी सार्वजनिक निकायों की वैधानिक शक्ति पर लागू किया गया है, और प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे से जुड़े रिपोर्ट किए गए मामलों का उच्च अनुपात इस सवाल से संबंधित है कि क्या किसी लेनदेन को स्पष्ट रूप से वैधानिक शक्तियों के प्रयोग के लिए उचित रूप से प्रासंगिक माना जाना चाहिए प्रदान किया गया।' उपरोक्त उद्धरण में 'जब तक कि स्पष्ट रूप से निषिद्ध न किया गया हो' शब्द यह दिखाने में बहुत मदद करते हैं कि जब तक सरकार को विधायिका द्वारा आकस्मिक कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक वह अपनी कार्यकारी शक्तियों में ऐसा कर सकती है...(पैरा 18) "

32. एसआर दास के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ (सुप्रा) शीर्ष अदालत के समक्ष अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। उनके आधिपत्य ने निम्नलिखित आदेश पारित करके उस याचिका का निपटारा किया: -

"इस आवंटन के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री एसआर दास, जो एक प्रधानाध्यापक हैं और उन्होंने एक घर बनाया है, और यह दर्शाया गया है कि उनके पास कोई अन्य भवन या घर नहीं है, इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में हम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हैं इस मामले में उच्च न्यायालय की। हालाँकि, हम उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता या अन्यथा पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। जहाँ तक श्री एसआर दास का संबंध है, यह निर्णय केवल इस मामले के तथ्यों से पुष्टि की जाती है। यह निर्णय जो इस मामले में अपील के अधीन है, अन्य व्यक्तियों के मामले भी उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए हैं या निपटाए गए हैं। हम केवल इस प्रतिवादी के मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दे रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता जिनके आवंटन उस निर्णय की विषय वस्तु हैं, यदि उन्हें सलाह दी जाती है, तो वे अपील कर सकते हैं, गुण-दोष के आधार पर और सीमा के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा। यह विशेष अनुमति याचिका पूर्वोक्त रूप से निपटाई जाती है। इस पर कोई आदेश नहीं होगा हस्तक्षेप आवेदन।"

33. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मात्र अवलोकन से, यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर एसआर दास के मामले में निर्णय की सत्यता की जांच नहीं की। इसलिए, उत्तरदाताओं और आपत्तिकर्ताओं के विद्वान वकील का यह तर्क कि एसआर दास के मामले में फैसले को विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन को किसी भी चुनौती के खिलाफ पूर्व न्यायिक माना जाना चाहिए, गलत धारणा के रूप में खारिज किया जाना चाहिए।

34. एसआर दास के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर सबसे गहन विचार करने के बाद, हम इससे सहमत हैं कि सरकार के पास अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए हुडा को निर्देश देने की शक्ति है। हम इससे भी सहमत हैं कि सरकार शहरी संपदा का विकास करते समय भूखंड का आरक्षण कर सकती है, लेकिन हम डिवीजन बेंच के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि अधिनियम की धारा 30 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 15 के तहत सरकार में निहित शक्तियां असीमित हैं. हमारी राय में, डिवीजन बेंच ने उस निष्कर्ष को दर्ज करने में गलती की है। जाहिर तौर पर इसने अधिनियम की धारा 15(1) के शुरुआती शब्दों और धारा 30(1) के अंतिम भाग को उचित सम्मान नहीं दिया। इन प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार केवल अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए हुडा को निर्देश दे सकती है और हुडा को निर्देश देने की सरकार की शक्तियां निरंकुश नहीं हैं। हम उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते जो सरकार दे सकती है; अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत निर्देश। बल्कि, ऐसे निर्देश न केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए बल्कि संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप भी होने चाहिए। इसलिए, हम डिवीजन बेंच के इस विचार को अस्वीकार करते हैं कि अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित शक्तियां असीमित हैं।

35. हमें उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति में कोई बल नहीं मिला। 2, 3 और 4 कि अधिनियम की धारा 15(1) या धारा 30(1) के तहत, मुख्यमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार एक विशेष प्रतिशत भूखंड आवंटित करने का पूर्ण विवेक प्राप्त है। किसी मामले में किसी वर्ग या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में भूखंडों को आरक्षित करने की नीति को अधिनियम के उद्देश्यों के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता है। सरकार के निर्देशों के तहत एक व्यक्ति को भूखंड का आवंटन भी किसी मामले में

उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन यह दलील कि पूर्ण विवेक एक व्यक्ति के पास हो सकता है, अधिनियम और संविधान की योजना के साथ पूरी तरह से असंगत है। इसी तरह, इस तर्क को भी नकारना होगा कि मुख्यमंत्री को प्रदत्त विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित है क्योंकि यह 'कानून के शासन' के सिद्धांत के विपरीत है जो भारतीय संविधान का मूल है। यह तर्क इसलिए भी अस्वीकार्य है क्योंकि हमारे देश में जनता के प्रतिनिधि चुनाव के समय जनता द्वारा जताए गए विश्वास के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं।

36. इस स्तर पर, हम मैक आइवर द्वारा "द मॉडर्न स्टेट" में 'राज्य' की सहमति के संबंध में दिए गए एक क्लासिक कथन पर ध्यान दे सकते हैं। विद्वान लेखक ने कहा:-

"कुछ लोगों के लिए राज्य अनिवार्य रूप से एक वर्ग-संरचना है, एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर प्रभुत्व रखने वाला संगठन है; अन्य इसे एक ऐसे संगठन के रूप में मानते हैं जो सभी वर्गों से परे है और पूरे समुदाय के लिए खड़ा है। वे इसे एक शक्ति प्रणाली के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है यह पूरी तरह से एक कानूनी संरचना के रूप में है, या तो पुराने ऑस्टिनियन अर्थ में जिसने इसे राज्यपालों और शासितों का संबंध बना दिया है, या, आधुनिक न्यायशास्त्र की भाषा में एक समुदाय के रूप में 'कानूनी नियमों के तहत कार्रवाई के लिए संगठित' है। कुछ लोग इसे इससे अधिक कुछ नहीं मानते हैं एक पारस्परिक बीमा समाज, अन्य हमारे पूरे जीवन की संरचना के रूप में। कुछ लोग राज्य को एक महान 'निगम' के रूप में वर्गीकृत करते हैं और अन्य इसे समाज से अप्रभेद्य मानते हैं।"

37. 'राज्य' की अवधारणा, जैसा कि इसे संविधान के प्रारंभ होने से पहले जाना जाता था और जैसा कि इसे संविधान के प्रारंभ होने के बाद लगभग दो दशकों तक समझा जाता था, हाल के वर्षों में भारी बदलाव आया है। आज राज्य की कल्पना केवल सत्ता का वज्र चलाने वाली एक दमनकारी मशीनरी के रूप में नहीं की जा सकती। आज सरकार विशेष सेवाओं की नियामक और प्रदाता है और नौकरियों, अनुबंधों, लाइसेंसों, कोटा, खनिज अधिकारों आदि सहित बड़े सार्वजनिक लाभ प्रदान करती है। सरकार खनन और अन्य उद्देश्यों के लिए मूल्यवान सैकड़ों और हजारों एकड़ भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण करती है। . सरकारी कार्यों के बढ़ते परिमाण और दायरे के साथ सरकारी उदारता के वितरण में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। कानून ने सरकारी कार्यों के बदलते चरित्र और व्यक्तिगत हित के साथ-साथ सार्वजनिक हित की रक्षा करने की आवश्यकता को भी मान्यता दी है। सरकार का विवेक असीमित नहीं माना गया है। सरकार अपने मनमाने विवेक से या अपनी इच्छा के अनुसार न तो दान दे सकती है और न ही रोक सकती है। सरकार को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह केवल कुछ व्यक्तियों के पक्ष में नौकरियां देगी या अनुबंध करेगी या परमिट या लाइसेंस जारी करेगी। इस संबंध में, बी. पुनानन थॉमस बनाम केरल राज्य , एआईआर 1969 केरल 81 (पूर्ण पीठ) मामले में मैथ्यू, जे. (तब वह थे) द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना लाभदायक होगा। उसने कहा:-

"सरकार अपनी उदारता के लिए प्राप्तकर्ताओं का चयन करने में एक व्यक्ति जितनी स्वतंत्र नहीं है और न ही उसे होना चाहिए। उसकी गतिविधियां जो भी हों, सरकार अभी भी सरकार है और एक लोकतांत्रिक समाज में अपनी स्थिति में निहित प्रतिबंधों के अधीन होगी। एक लोकतांत्रिक सरकार उन व्यक्तियों की पसंद के लिए मनमाने और सनकी मानक नहीं बना सकते जिनके साथ यह अकेले व्यवहार करेगा।"

यह पारंपरिक दृष्टिकोण कि कार्यपालिका जवाबदेह नहीं है, जहां उसका कार्यकारी कार्य विशेषाधिकार शक्ति के कारण होता है, लंबे समय से खारिज कर दिया गया है। प्रो. एचडब्ल्यूआर वेड ने अपने कार्य 'प्रशासनिक कानून' के छठे संस्करण में निम्नलिखित शब्दों में सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों की शक्तियों के बीच अंतर किया है:-

"... अब तक उल्लिखित सभी प्राधिकारियों का सामान्य विषय यह है कि पूर्ण या निरंकुश विवेक की धारणा को अस्वीकार कर दिया गया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रदत्त वैधानिक शक्ति विश्वास पर प्रदान की जाती है, बिल्कुल नहीं - यानी, यह कहा जा सकता है वैध रूप से केवल सही और उचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे प्रदान करते समय संसद का इरादा माना जाता है। हालांकि क्राउन के वकीलों ने कई मामलों में तर्क दिया है कि अप्रतिबंधित अनुज्ञेय भाषा निरंकुश विवेक प्रदान करती है, सच्चाई यह है कि, नियम पर आधारित प्रणाली में कानून की दृष्टि से निरंकुश सरकारी विवेक एक विरोधाभास है।"

प्रो. वेड ने आगे कहा:-

"..... निरंकुश विवेक की पूरी अवधारणा एक सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अनुचित है, जिसके पास केवल इसलिए शक्तियां होती हैं ताकि वह उनका उपयोग जनता की भलाई के लिए कर सके।

ऐसी कानूनी सीमाएं लागू करने में कुछ भी विरोधाभासी नहीं है। यह वास्तव में विरोधाभासी होगा यदि उन्हें थोपा न गया हो। न ही यह सिद्धांत ब्रिटिश या अमेरिकी कानून की कोई विचित्रता है; यह फ्रांसीसी कानून में भी उतना ही प्रमुख है। न ही यह कोई विशेष प्रतिबंध है जो केवल स्थानीय अधिकारियों पर लागू होता है: यह क्राउन के मंत्रियों पर भी कम लागू नहीं होता है। न ही यह प्रशासन के क्षेत्र तक ही सीमित है: यह वहां काम करता है जहां किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विवेक दिया जाता है, उदाहरण के लिए जहां एक न्यायाधीश के पास जूरी ट्रायल का आदेश देने का विवेक होता है। केवल वहीं जहां अधिकार प्राप्त व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्तियां दी जाती हैं वहां विवेक पूर्ण होता है। स्पष्टतः इसका सार्वजनिक कानून में कोई उपयोग नहीं हो सकता।

इन्हीं कारणों से सैद्धांतिक तौर पर समीक्षाहीन प्रशासनिक विवेक जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जो कि निरंकुश विवेक के संदर्भ में उतना ही विरोधाभास होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए वह यह है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या है, और कुछ विशेष मामलों में विवेकाधीन निर्णयों की समीक्षा की गुंजाइश न्यूनतम हो सकती है। यह स्वयंसिद्ध है कि सभी विवेक का दुरुपयोग किया जा सकता है, और हर शक्ति की कानूनी सीमाएँ कहीं न कहीं पाई जाती हैं।" (रेखांकित करना हमारा है)।

38. पैडफील्ड बनाम कृषि, मत्स्य और खाद्य मंत्री, (1968) एसी 997 में, प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। मंत्री ने दुग्ध विपणन बोर्ड के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने से इनकार कर दिया था कि बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने दूध की कीमतें इस तरह से तय की थीं जो शिकायतकर्ताओं के लिए अनुचित थीं। मंत्री का निर्णय इस कारण पर आधारित था कि यदि उन्होंने समिति के निर्णय को लागू नहीं करने का निर्णय लिया तो यह उनके लिए राजनीतिक रूप से शर्मनाक होगा। पूर्ण विवेक के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए लॉर्ड रीड ने कहा:-

"संसद ने इस इरादे से विवेक प्रदान किया होगा कि इसका उपयोग अधिनियम की नीति और उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए; अधिनियम की नीति और उद्देश्यों को अधिनियम को समग्र रूप से समझकर निर्धारित किया जाना चाहिए और निर्माण हमेशा कानून का विषय है न्यायालय के लिए। इस प्रकार के किसी मामले में कोई सख्त रेखा खींचना संभव नहीं है, लेकिन यदि मंत्री, अधिनियम की गलत व्याख्या करने के कारण या किसी अन्य कारण से, अपने विवेक का उपयोग विफल करने या चलाने के लिए करता है अधिनियम की नीति और उद्देश्यों के विपरीत, यदि पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की सुरक्षा के हकदार नहीं होंगे तो हमारा कानून बहुत दोषपूर्ण होगा।"

39. ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन, (1971) 2 क्यूबी 175 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियों पर विचार करते हुए, लॉर्ड डेनिंग एमआर ने कहा: -

"एक वैधानिक निकाय का विवेक कभी भी निरंकुश नहीं होता है। यह एक विवेक है जिसका प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका मतलब कम से कम यह है: वैधानिक निकाय को प्रासंगिक विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए न कि अप्रासंगिक रूप से। इसका निर्णय इससे प्रभावित होता है ऐसे अनावश्यक विचार जिन्हें ध्यान में नहीं रखना चाहिए था, तो निर्णय टिक नहीं सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैधानिक निकाय ने अच्छे विश्वास में काम किया है; फिर भी निर्णय को रद्द कर दिया जाएगा। यह पैडफील्ड बनाम कृषि मंत्री द्वारा स्थापित किया गया है, मत्स्य पालन और भोजन जो आधुनिक प्रशासनिक कानून में एक मील का पत्थर है।"

40. लेकर एयरवेज लिमिटेड बनाम व्यापार विभाग, 1977 क्यूबी 643 में, लॉर्ड डेनिंग ने युद्ध के समय क़ानून में विशिष्ट प्रावधानों को खारिज करते हुए नागरिक उड्डयन अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मंत्री के विशेषाधिकार पर चर्चा की और कहा: -

"यह देखते हुए कि विशेषाधिकार जनता की भलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विवेक शक्ति है, यह इस प्रकार है कि इसके प्रयोग की जांच न्यायालयों द्वारा की जा सकती है जैसे कि अन्य विवेकाधीन शक्ति जो कार्यपालिका में निहित है।"

41. एससी जयसिंघानी बनाम भारत संघ , एआईआर 1967 एससी 1427 में समानता के सिद्धांत के साथ असंगत होने के कारण निरंकुश विवेक के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था, जिसमें रामास्वामी, जे. ने कहा था: -

"इस संदर्भ में इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन की पहली अनिवार्यता है जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था आधारित है। कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली में, विवेक, जब कार्यकारी अधिकारियों को प्रदान किया जाता है, स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर ही सीमित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कानून के शासन का मतलब है कि निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों के आवेदन द्वारा किए जाने चाहिए और सामान्य तौर पर, ऐसे निर्णय पूर्वानुमानित होने चाहिए और नागरिक को पता होना चाहिए कि वह कहां है। यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत के या बिना किसी नियम के लिया जाता है तो यह अप्रत्याशित होता है और ऐसा निर्णय कानून के शासन के अनुसार लिए गए

निर्णय का विरोधी होता है। (देखें डाइसी - "संविधान का कानून" - दसवां संस्करण, परिचय) उदा.) संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम अंडरलिक (1951-342 यूएस 98:96 लॉ एड 113) में डगलस, जे. ने कहा, 'कानून अपने सर्वोत्तम क्षणों तक पहुंच गया है', "जब इसने मनुष्य को कुछ शासकों के असीमित विवेक से मुक्त कर दिया है ..... जहां विवेक पूर्ण है, वहां मनुष्य को सदैव कष्ट सहना पड़ता है।' इसी अर्थ में कानून के शासन को सनक का कट्टर शत्रु कहा जा सकता है। विवेक, जैसा कि लॉर्ड मैन्सफील्ड ने जॉन विल्क्स (1770-98 ईआर 327) के मामले में क्लासिक शब्दों में कहा था, का अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित ठोस विवेक। इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, हास्य से नहीं, यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए"

42. 'पूर्ण विवेक' और न्यायिक समीक्षा से छूट के तर्क की अस्वीकृति श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम यूपी राज्य , एआईआर 1991 एससी 537 के ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है: -

".... हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान प्रस्तावना में प्रस्तावित आदर्शों के विपरीत अपनी गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में राज्य के कार्यों में अनुचितता या अनुचितता की परिकल्पना या अनुमति नहीं देता है। हमारी राय में, यह संवैधानिक योजना से अलग होगा संविदात्मक मामलों में अनुच्छेद 14 के बहिष्कार के तर्क को स्वीकार करना। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा और स्वीकार्य आधार और जो राहत मिल सकती है वह अलग-अलग मामले हैं लेकिन यह इसके पूर्ण बहिष्कार के दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराता है। यह अधिक है इसलिए जब आधुनिक प्रवृत्ति ऐसे अनुबंधों में किसी शब्द की अनुचितता की जांच करने की भी है जहां सौदेबाजी की शक्ति असमान है, तो ये बातचीत के अनुबंध नहीं हैं बल्कि असमान लोगों के बीच मानक अनुबंध हैं।

xx xx xx xx यह मानते हुए भी कि कला को आकर्षित करने के लिए राज्य की कार्रवाई में कुछ सार्वजनिक तत्व की उपस्थिति की अवधारणा को आयात करना आवश्यक है। 14 और न्यायिक समीक्षा की अनुमति देते हुए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य या सार्वजनिक निकाय के सभी कार्यों का अंतिम प्रभाव निस्संदेह सार्वजनिक हित पर पड़ता है, इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित सार्वजनिक तत्व संविदात्मक मामलों में भी मौजूद है। इसलिए, हमें अनुबंध के बाद अनुबंध संबंधी मामलों में राज्य की कार्रवाइयों को कला के आधार पर इसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना मुश्किल और अवास्तविक लगता है। 14.....' अब और नहीं हो सकता इस समय संदेह है कि कला. भारत के संविधान की धारा 14 सरकारी नीति के मामलों पर भी लागू होती है और यदि सरकार की नीति या कोई कार्रवाई, यहां तक कि संविदात्मक मामलों में भी, तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है, तो यह असंवैधानिक होगी । (देखें रमण दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) 3 एससीआर 1014: (एआईआर 1979 एससी 1628) और कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1980) 3 एससीआर 1338: (एआईआर 1980 एससी 1992)), कर्नल एएस सांगवान बनाम भारत संघ , 1980 (सप्लीमेंट) एससीसी 559: (एआईआर 1981 एससी 1545) में, जबकि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में नीति को बदलने का विवेकाधिकार था, जब क़ानून या नियम को रौंदा नहीं गया था। इसे व्यापक माना गया, संविधान के अनुच्छेद 14 में इसे अनिवार्य और अंतर्निहित बताया गया कि नीति में बदलाव निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए और यह आभास नहीं देना चाहिए कि यह मनमाने ढंग से या किसी गुप्त मानदंड से किया गया है। अनुच्छेद 14 और राज्य की गतिविधि के क्षेत्र की परवाह किए बिना, इस कसौटी पर इसकी वैधता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली प्रत्येक राज्य कार्रवाई की आवश्यकता लंबे समय से तय की गई है। इस न्यायालय के बाद के फैसलों ने इस सिद्धांत की नींव को मजबूत किया है और यह होगा इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय के केवल दो हालिया निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।"

43. इसी तरह, एलआईसी ऑफ इंडिया और अन्य में। वी. उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र और अन्य, जेटी 1995(4) एससी 366, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा से राज्य की कार्रवाई की छूट के दावे को खारिज कर दिया और कहा: -

"... सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक हित में कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रत्येक कार्रवाई या उसके कार्य सार्वजनिक तत्व को जन्म देते हैं, उन्हें सार्वजनिक हित द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। यह सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग है या सार्वजनिक तत्व से जुड़ी कार्रवाई खुली हो जाती है चुनौती देना। यदि यह दिखाया जाता है कि शक्ति का प्रयोग मनमाना, अन्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण है तो राज्य, उसके साधन, सार्वजनिक प्राधिकरण या उस व्यक्ति के लिए कोई जवाब नहीं होना चाहिए जिसके कृत्यों में यह कहने के लिए सार्वजनिक तत्व का प्रतीक है कि उनके कार्य निजी कानून के क्षेत्र में और वे अपने कार्यों में कोई भी शर्त या सीमा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जैसा कि निजी नागरिक, समानार्थी, निजी कानून के क्षेत्र में करते हैं। इसके कार्य कुछ तर्कसंगत और प्रासंगिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। इसे निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए पारंपरिक या अप्रासंगिक विचार.....

इस न्यायालय ने एक उपकरण या राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उसकी कार्रवाई निजी कानून के क्षेत्र में है और अनुच्छेद 14 के तहत निर्धारित परीक्षणों को पूरा करने से मुक्त होगी। सार्वजनिक कानून और निजी कानून के अधिकारों और उपचारों के बीच विरोधाभास, हालांकि नहीं हो सकता है किसी भी सीधे जैकेट फार्मूले द्वारा मिटाया गया, यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा। इसलिए, किसी अनुबंध से उत्पन्न विवाद का निर्णय किसी दिए गए मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सार्वजनिक कानून उपाय और दायर निजी कानून के बीच अंतर को सटीकता से सीमांकित नहीं किया जा सकता है। विवाद की गतिविधि, दायरे और प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रत्येक मामले की उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी। सार्वजनिक कानून और निजी कानून उपचार के बीच अंतर अब बहुत पतला और व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया है...

संविदात्मक संबंधों के क्षेत्र में राज्य, उसके साधन, सार्वजनिक प्राधिकरण या जिनके कार्य सार्वजनिक तत्व, सार्वजनिक कर्तव्य या दायित्व के प्रतीक हैं, उन्हें निष्पक्ष, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से कार्य करने का आदेश दिया जाता है, निष्पक्ष रूप से सभी प्रासंगिक विचार करने के बाद विकल्पों पर विचार करना और इस तरीके से जो सार्वजनिक भलाई और सामान्य सार्वजनिक हित के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित, प्रासंगिक और सार्थक हो और इसे अपने निर्णय में किसी भी अप्रासंगिक या तर्कहीन कारकों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए या मनमाने ढंग से नहीं लेना चाहिए। निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य अनुच्छेद 14 और 21 के तहत परिकल्पित निष्पक्ष प्रक्रिया का हिस्सा है। सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक कर्तव्य या दायित्व के तहत आने वालों की प्रत्येक गतिविधि को कारण से सूचित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक हित द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।"

44. मामले के इस पहलू को करीब लाने से पहले, हम नई दिल्ली पब्लिक स्कूल और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। आदि बनाम हुडा और अन्य। आदि, जेटी 1996(7) एससी 103। यह निर्णय शीर्ष अदालत द्वारा सेवन सीज़ एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य में इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर दिया गया है। बनाम हुडा, (1996-2)113 पीएलआर17 जिसमें इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने हुडा द्वारा किए गए आवंटन को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए, उनके आधिपत्य ने अधिनियम की धारा 15 और विनियम 3, 4 और 5 का संदर्भ दिया और कहा: -

"... विशेष रूप से विनियम 3 (सी) के साथ पढ़ी गई धारा 15 (3) को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हुडा द्वारा अर्जित संपत्ति के निपटान के कई तरीके हैं। संपत्ति के हस्तांतरण के तरीकों में से एक जैसा कि विनियम 5 के उप-विनियम (सी) के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (3) में दर्शाया गया है, सार्वजनिक नीलामी, आवंटन या अन्यथा है। जब सार्वजनिक प्राधिकरण अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है तो "अन्यथा" शब्द को सुसंगत माना जाएगा सार्वजनिक उद्देश्य और स्पष्ट और सुस्पष्ट दिशानिर्देश या नियम आवश्यक हैं और सार्वजनिक अधिकारियों की इच्छा और इच्छा के तहत या उनकी आड़ में किसी बाहरी विचार के लिए नहीं। यह योजना की प्रकृति और सार्वजनिक उद्देश्य की वस्तु पर निर्भर करेगा। हासिल किया जाना चाहिए। सभी मामलों में प्रासंगिक मानदंड विशिष्ट नियमों या विनियमों द्वारा पूर्व-निर्धारित किया जाना चाहिए और जनता के लिए प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसलिए, सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक विशिष्ट नियम या वैध दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा, लाभकारी प्रक्रिया सार्वजनिक नीलामी द्वारा होगी। इसलिए, डिवीजन बेंच ने सही ही कहा है कि ऐसे वैधानिक नियमों के अभाव में निजी संस्थानों या व्यक्तियों को साइट आवंटित करने की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कानून में सही नहीं था।"

45. इसलिए, हम प्रतिवादियों के विद्वान वकील के इस तर्क को खारिज करते हैं कि अपने विवेक और पसंद के अनुसार भूखंडों का आवंटन करने की पूर्ण शक्ति मुख्यमंत्री में निहित हो सकती है और इस तरह के विवेक को कसौटी पर न्यायिक जांच से छूट दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और अन्य प्रावधान।

फिर भी, हम दोहरा सकते हैं कि अधिनियम की धारा 30(1) के तहत हुडा को भूखंड आरक्षित करने के निर्देश देने की सरकार की शक्तियों का उपयोग एक समूह के रूप में प्रतिष्ठित पेशेवरों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों आदि के पक्ष में किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा आरक्षण हो। अधिनियम के मापदंडों, योजना और उद्देश्यों के भीतर है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में भूखंड आरक्षित करने का हुडा द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय इसी श्रेणी में आता है। साथ ही, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पेशेवरों आदि के लिए आरक्षित भूखंडों को सरकार/हुडा द्वारा बनाई गई नीति का विज्ञापन जारी करने के बाद ही आवंटित किया जा सकता है और आवंटन निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट (सुप्रा)।

46. पुन: क्या मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित मानदंड अस्पष्ट, मनमाना है और इसलिए असंवैधानिक है।

इस सिद्धांत को खारिज करने के बाद कि भूखंडों के आवंटन के लिए पूर्ण विवेकाधिकार मुख्यमंत्री के पास है, अब हम जांच करेंगे कि क्या विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों को आवंटित करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्धारित मानदंड असंवैधानिक हैं। हमारे द्वारा इस मुद्दे की जांच इस धारणा पर की जा रही है कि सरकार के विवेक पर कम से कम 5% भूखंड रखने का उत्तरदाताओं का निर्णय संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। उत्तरदाताओं और आपत्तिकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' की अभिव्यक्ति में 'प्रतिष्ठित' और 'जरूरतमंद' शब्दों के बीच आने वाले शब्द 'और' की व्याख्या 'या' के रूप में की जानी चाहिए। श्री सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के 21.11.1990 के नोट को मानदंड नहीं कहा जा सकता है जो वास्तव में अनुबंध आर 2 के साथ पढ़े गए अनुबंध आर 14 से वर्णित है। श्री सिब्बल की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि हरियाणा राज्य के साथ-साथ हुडा भी एक स्पष्ट रुख के साथ सामने आया है कि एसआर दास के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के बाद, सरकार ने रद्दीकरण पत्र दिनांक 29.6.6 को वापस ले लिया। 1987. इसके बाद, इस मुद्दे की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि भूखंडों को जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों को कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन आवंटित किया जाएगा। हुडा के मुताबिक यह फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की. यहां तक कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दायर जवाब में भी यह दलील नहीं दी गई है कि 21.11.1990 को दर्ज नोट में भूखंडों के आवंटन के मानदंड शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, अनुलग्नक आर 2 पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि यह महज़ हुडा कार्यालय द्वारा अपनी बैठक में विचार के लिए तैयार किया गया एक प्रस्ताव था। हुडा द्वारा 14.8.1987 को आयोजित बैठक में पारित अंतिम प्रस्ताव को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि बैठक में रखे गए एजेंडे को उस रूप में अनुमोदित नहीं किया गया जिस रूप में उसे प्रस्तुत किया गया था।

47. उत्तरदाताओं और आपत्तिकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क कि 'और' प्रतिष्ठित 'और' जरूरतमंद 'शब्दों के बीच आने वाले शब्द को' या 'के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, इस आधार पर आधारित है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति जरूरतमंद नहीं हो सकता है वह व्यक्ति जिसने राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला, विज्ञान, संगीत, खेल, साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो, वह भूखंड के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री को आवेदन करना अपनी गरिमा से नीचे समझ सकता है। इसी प्रकार, एक व्यक्ति जो जरूरतमंद हो सकता है, लेकिन जीवन के किसी भी क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित नहीं कर पाया हो, लेकिन विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क कर सकता है। यह तर्क काफी आकर्षक प्रतीत होता है लेकिन बारीकी से जांच करने पर हमें इसमें कोई दम नजर नहीं आता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भौतिक लाभ, जैसे जमीन का टुकड़ा, इस उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना चाहेगा, लेकिन एक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। यदि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने का निर्णय लेती है, जिसने राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है और वह हरियाणा राज्य में बसना चाहता है, तो वह औपचारिक आवेदन की आवश्यकता के बिना हुडा को प्लॉट आवंटित करने का निर्देश दे सकती है। हालाँकि, अगर हम 'और' शब्द के स्थान पर 'या' शब्द पढ़ेंगे तो दिनांक 21.11.1990 के नोट में शामिल मानदंड एक मजाक बनकर रह जाएंगे। ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं जिन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी असाधारण नहीं किया हो, लेकिन उन्हें अभी भी भूखंडों की आवश्यकता हो सकती है। अगर इन सभी लोगों को उनकी जरूरत के आधार पर प्लॉट आवंटित कर दिए जाएं तो शायद मुख्यमंत्री को सभी शहरी संपदाओं में पूरी जमीन आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अन्यथा उसे उदारता प्रदान करने के लिए अपनी पसंद के व्यक्तियों को चुनना होगा। इस तरीके से सत्ता का प्रयोग संविधान के साथ पूर्ण धोखाधड़ी होगी।

48. एक और कारण है कि विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त 'और' शब्द को 'या' के रूप में पढ़ा जाए। 'या' शब्द सामान्यतः वियोजक है और 'और' शब्द सामान्यतः संयोजक है। निगमन के उद्देश्य से, यदि शब्दों को शाब्दिक रूप से पढ़ने से अस्पष्ट या बेतुके परिणाम मिलते हैं तो इन शब्दों को आपस में बदला जा सकता है। हालाँकि, ऐसे पाठ्यक्रम को आसानी से नहीं अपनाया जा सकता है। मर्सी डॉक्स और हार्बर बोर्ड बनाम हेंडरसन ब्रदर्स, (1888)13 एसी 595 (एचएल) में, लॉर्ड हैल्सबरी ने कहा:-

"...'या' को 'और' के रूप में पढ़ना तब तक बहाल नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसी क़ानून के स्पष्ट इरादे के किसी अन्य भाग के लिए ऐसा करने की आवश्यकता न हो।"

ग्रीन बनाम प्रीमियर ग्लिनरहोन-ए स्लेट कंपनी, (1928)1 केबी 561, स्क्रूटन, एलजे में कहा गया है:-

"आप कभी-कभी किसी क़ानून में 'या' को 'और' के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन, आप ऐसा तब तक नहीं करते हैं जब तक कि आप बाध्य न हों क्योंकि 'या' का मतलब आम तौर पर 'और' नहीं होता है और 'और' का मतलब आम तौर पर 'या' नहीं होता है। "

49. जिस संकीर्ण मुद्दे पर अब विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या मानदंड, अर्थात् 'जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' को वैध मानदंड माना जा सकता है। न तो 'प्रतिष्ठित' शब्द और न ही 'जरूरतमंद' शब्द को

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित किया गया है और न ही मामले के रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से उनका उच्चारण किया गया है। एजेंडा नोट (अनुलग्नक आर2) में फाइल पर दर्ज तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए दिनांक 14.7.1971 के कुछ निर्णय का संदर्भ दिया गया है। उस निर्णय के अनुसार, सेक्टर 21, फ़रीदाबाद में 15% भूखंड हरियाणा विधानसभा के सदस्यों और संसद सदस्यों के लिए और कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे राजनीतिक पीड़ित, लेखक, पत्रकार और अन्य योग्य व्यक्तियों को आवंटन के लिए आरक्षित किए गए थे। हालाँकि, इस याचिका के रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि हुडा ने राजनीतिक पीड़ितों, प्रतिष्ठित लेखकों, पत्रकारों आदि को भूखंड आवंटित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि यह प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित है और भूखंड आवंटन के उद्देश्य से जरूरतमंदों का निर्धारण मुख्यमंत्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। प्रतिष्ठित और जरूरतमंद कौन हैं, इस प्रश्न के निर्धारण के लिए किसी भी दिशा-निर्देश के पूर्ण अभाव के कारण, यह मुख्यमंत्री की इच्छाशक्ति पर छोड़ दिया गया है कि उन्हें एक प्रतिष्ठित और जरूरतमंद व्यक्ति मानकर भूखंड आवंटित किया जाए। मानदंड यह नहीं कहता है कि आवेदक/भावी आवंटी ने राष्ट्रीय हित या राज्य के हित की सेवा करके खुद को प्रतिष्ठित किया होगा या उसे विज्ञान, कला, खेल, संगीत, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर साहित्य या उसके समान। यह इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मुख्यमंत्री यह कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई व्यक्ति जरूरतमंद है या नहीं। आय का कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटा के तहत सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती करते समय उम्मीदवार के पास खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य या जिला स्तर पर उसकी उपलब्धि को दर्शाने वाला एक विशेष ग्रेड का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पारिवारिक आय का मानदंड विकसित किया गया है। विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड आवंटित करने की शक्ति के प्रयोग के लिए ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं बनाया गया है। कोई नियम या विनियम नहीं बनाया गया है और न ही कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है जिसका पालन करके मुख्यमंत्री यह निर्धारित कर सकें कि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित और जरूरतमंद है। सब कुछ मुख्यमंत्री के निरंकुश विवेक पर छोड़ दिया गया है। इस तरह की बेलगाम और अनियंत्रित शक्ति प्रदान करना स्पष्ट रूप से ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य , एआईआर 1974 एससी 555 मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित समानता के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या के खिलाफ है; मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एआईआर 1978 एससी 597 और कई अन्य निर्णय जिनमें से कुछ पर सेवन सीज़ एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य की डिवीजन बेंच ने भरोसा किया है। वी. हुडा और अन्य। (सुप्रा) और हरि राम सिंगला बनाम हरियाणा राज्य , 1994 पीएलजे 230 में। इस मामले के तथ्यों से मानदंडों की मनमानी काफी हद तक प्रदर्शित होती है। जैसा कि आगे देखा जायेगा, मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी आदेश में विशिष्ट एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को मापदंड के तहत भूखण्ड आवंटन का आदेश नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विशेष प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक द्वारा पारित किसी भी आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि आवेदक को विवेकाधीन कोटेशन के तहत भूखंड आवंटित किया जा रहा है। उसके साथ एक प्रतिष्ठित और जरूरतमंद व्यक्ति का व्यवहार करके। यहां तक कि आवंटन के 8000 से अधिक मामलों (1991 से मार्च, 1996 के बीच) में से अधिकांश में दायर आवेदन में आवेदकों ने यह नहीं बताया है कि वे प्रतिष्ठित और जरूरतमंद व्यक्ति हैं। बल्कि आवेदन इस सरल प्रार्थना के साथ दायर किए गए हैं कि आवेदक को मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंड आवंटित किया जाए और ऐसे आवेदन पर, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हुडा को एक विशेष भूखंड आवंटित करने का निर्देश देते हुए आदेश दर्ज किया गया है। आवेदक को. यह स्पष्ट रूप से 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' के मानदंडों की अस्पष्टता का संकेत है। अस्पष्ट और मनमाने मानदंडों का लाभ उठाते हुए, अधिकांश आवेदकों, जिन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित नहीं किया है, को बड़े या छोटे भूखंडों के रूप में उदारता से सम्मानित किया गया है। कुछ मामलों में, एक ही परिवार के सदस्यों को दो या दो से अधिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन के कुछ लाभार्थियों के पास दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में आलीशान घर हैं। इन्हें एक से दो कनाल के बड़े प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इसलिए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि अनुबंध R11 में शामिल मानदंड अस्पष्ट और मनमाने हैं। इसने मुख्यमंत्री को भूखंड आवंटित करने के लिए असीमित, अनियंत्रित और बेलगाम विवेकाधिकार प्रदान किया, बिना इस बात पर विचार किए कि कोई व्यक्ति वास्तव में प्रतिष्ठित और जरूरतमंद है या नहीं।

50. पुन: 5% की सीमा का उल्लंघन.

मुख्यमंत्री के विवेक पर आरक्षित 5% कोटा से अधिक भूखंडों के आवंटन के मुद्दे पर, हुडा की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यद्यपि हाल के वर्षों में किए गए आवंटन 5% की सीमा से अधिक होने की अपील कर सकते हैं, लेकिन यदि विवेकाधीन कोटा के तहत अआवंटित भूखंडों के कुल समर्थन को ध्यान में रखा जाता है, उत्तरदाताओं पर 5% की सीमा से अधिक होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। श्री सरीन के तर्क पर गहन विचार करने के बाद भी हम उनसे सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 5 प्रतिशत से अधिक भूखंड आवंटित नहीं किये हैं। इस संबंध में, हम उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 की ओर से 24.7.1996 को दायर किए गए उत्तर का उल्लेख कर सकते हैं। प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 3 (सी) में, उत्तरदाताओं ने कहा है कि विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन की नीति शुरू में फरीदाबाद और पंचकुला में भूखंडों पर लागू की गई थी और बाद में इसे पूरे हरियाणा राज्य में विस्तारित किया गया था। उत्तरदाताओं ने यह भी कहा है कि विवेकाधीन कोटा से आवंटित भूखंड निम्नलिखित चार स्रोतों से आए थे: -

(i) नये बनाये गये भूखंडों का 5%;

(ii) सभी पुन: प्रारंभ किए गए या अभ्यर्पित किए गए भूखंड;

(iii) सभी रद्द किए गए प्लॉट जो प्रारंभिक राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हो गए; और

(iv) सभी अनावंटित भूखंड।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नव निर्मित भूखंडों में से 5% के अलावा, बड़ी संख्या में सरेंडर/रद्द और अनाबंटित भूखंड हैं। मुख्यमंत्री के विवेक के अनुसार आवंटित करने के लिए उनके निपटान में रखा गया है। उत्तर दिनांक 24.7.1996 के पैरा 2 में उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 ने कहा है कि पिछले छह महीनों में किए गए 4407 के कुल आवंटन में से 1842 भूखंड विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटित किए गए थे। उसी उत्तर के पैरा 12 में, कुल प्लॉटेशन के आंकड़े 2662 दिए गए हैं। यदि हम उत्तर के पैरा 7 में दिए गए कथनों के अनुसार सरल गणित पर जाएं, तो मुख्यमंत्री ने कुल भूखंडों का 40% से अधिक आवंटित किया। छह महीने के दौरान विवेकाधीन कोटा के तहत। यदि हम पैरा 12 में दिए गए कथनों के अनुसार चलें, तो विवेकाधीन कोटा के तहत कुल आवंटन 60% से अधिक है। इस प्रकार, हम श्री सेठी के इस तर्क में दम पाते हैं कि विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों का आवंटन नीतिगत निर्णय के अनुसार निर्धारित कुल भूखंडों के 5% से कहीं अधिक किया गया है और इस तरह के अतिरिक्त आवंटन पूरी तरह से अनुचित हैं। हमारे विचार में, प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के साथ-साथ एचयूडी ए द्वारा पारित प्रस्ताव की स्पष्ट रूप से अवहेलना की और नीति के इस पेटेंट उल्लंघन के लिए किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में प्रतिवादी की कार्रवाई की गई। नंबर 3 को मनमाना और असंवैधानिक कहा जा सकता है।

51. अब हम श्री सेठी के इस तर्क से निपटेंगे कि उत्तरदाताओं ने एक तंत्र का आविष्कार किया ताकि एक ही परिवार को एक से अधिक भूखंडों के आवंटन को सक्षम किया जा सके। विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि एक ही परिवार को एक से अधिक भूखंड के आवंटन के खिलाफ अनुबंध आर 11 और अनुबंध आर 14 में शामिल तथाकथित प्रतिबंध हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर नजर डालने से पता चलता है कि यदि आवेदक के पास अपने नाम पर या पत्नी और आश्रित बच्चों सहित परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई घर या भूखंड है, तो विवेकाधीन कोटे के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता है। वही शहरी संपदा. पंचकुला की शहरी संपत्ति के संबंध में, एक अतिरिक्त प्रतिबंध शामिल किया गया था, अर्थात् आवेदक के पास चंडीगढ़ या मोहाली में कोई घर या भूखंड नहीं होना चाहिए और इसके अलावा आवेदक को किसी भी शहरी क्षेत्र में विवेकाधीन कोटा के तहत आवासीय भूखंड आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी और बच्चों सहित उसके परिवार के सदस्यों में से किसी एक के नाम पर संपत्ति। इससे एक ही परिवार के सदस्यों को एक से अधिक शहरी संपदा में आवंटन की पर्याप्त गुंजाइश बच गई। विद्वान वकील ने यह प्रदर्शित करने के लिए हमारे सामने बीस से अधिक उदाहरण उद्धृत किए हैं कि एक ही परिवार को विवेकाधीन कोटा के तहत एक से अधिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में मकान रखने वाले लोगों को आवंटित किए गए प्लॉटों का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि भूखंडों को विवेकाधीन कोटा के तहत मानदंडों का ध्यान रखे बिना और विवेकाधीन कोटा से कहीं अधिक आवंटित किया गया था।

52. पुन: प्रभावशाली व्यक्तियों/उनके वार्डों को भूखंडों का आवंटन।

विद्वान वकील का तर्क है कि कई प्रभावशाली लोग फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला की शहरी संपदा में बड़े भूखंड खरीदने में सक्षम हैं, जहां भूखंडों की कीमतें उन कीमतों से तीन से चार गुना अधिक हैं, जिन पर भूखंड आवंटित किए गए हैं। जांच कराएं। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के जवाब में हुडा की ओर से पेश वकील ने विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा पिछले दस वर्षों (1.4.1986 से 24.3.1996 तक) के दौरान किए गए विभिन्न आवंटनों का संकलन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तियों को भूखंडों के आवंटन देने वाली छोटी सूचियाँ भी तैयार कीं। विद्वान वकील ने भूखंडों (10 मरला से 2 कनाई) के आवंटन के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी प्रस्तुत किए। उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत सूचियों से जो कुछ तथ्य सामने आए हैं, वे नीचे सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं: -

क्रम संख्या व्यक्तियों की श्रेणी भूखंडों की संख्या शहरी संपत्ति का नाम आवंटन की अवधि भूखंडों का आकार टिप्पणियाँ

1. संसद सदस्य/उनके वार्ड फ़रीदाबाद (6) गुड़गांव (38) पंचकुला (6) शेष अन्य शहरी सम्पदाएं दो मामलों को छोड़कर 1991 से 1996 तक भिन्न हैं। उनमें से आठ को वर्ष 1996 में 6 मार्लास्टो2 कनाल आवंटित किए गए हैं, इनमें से अधिकांश हरियाणा राज्य के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित हैं।

2. विधान सभाओं के सदस्य/उनके वार्ड, उनमें से अधिकांश शहरी संपदा में 1991 से 1996 8 मरला से 2 कनाल तक, कुछ विधायक राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात, नागालैंड से संबंधित हैं।

3. उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीश/उनके वार्ड जिनमें से अधिकांश फ़रीदाबाद में हैं। गुड़गांव और पंचकुला.

1991 से 1996 10 मरला 2 कनाल

4. आईएएस अधिकारी/उनके वार्ड, उनमें से अधिकांश फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में 1991 से 1996 10 मरला से 2 कनाल

5. आईपीएस अधिकारी/उनके वार्ड फ़रीदाबाद(8) गुड़गांव(22) पंचकुला(10) बाकी अन्य शहरी संपदा में।

1991 से 1996 8 मरला से 2 कनाल

6. एचसीएस अधिकारी/उनके वार्ड।

उनमें से अधिकांश गुड़गांव, फ़रीदाबाद और पंचकुला में 1001 से 1996 तक 6 मरला से 1 कनाल तक।

7. लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य/उनके वार्ड।

फ़रीदाबाद(1) गुड़गांव (6) पंचकुला (1) करनाल (2) 1991 से 1996 14 मरला से 2 कनाल

8. एसएसएसडी के सदस्य/उनके वार्ड।

फ़रीदाबाद (2) गुड़गांव (4) पंचकुला (2) बाकी अन्य शहरी संपदा में।

1991 से 1996 10 मरला से 2 कनाल हुडा के अधिकारी/कर्मचारी/उनके वार्ड।

उनमें से अधिकांश गुड़गांव, फ़रीदाबाद, पंचकुला और करनाल में हैं।

1991 से 1996 तक 2 मरला से 1 कनाल तक के प्लॉट निचले स्तर के कर्मचारियों को 2 से 4 मरला तक के प्लॉट मिले हैं, लेकिन जिन्हें महत्वपूर्ण पद मिला है, उन्होंने 10 मरला से 1 कनाल तक के प्लॉट खरीदे।

10. रक्षा कर्मी/उनके वार्ड।

फ़रीदाबाद (13) गुड़गांव (47) पंचकुला (16) बाकी अन्य शहरी संपदा में।

1991 से 1996 14 मरला से 2 कनाल

53. हुडा ने कुछ ऐसे व्यक्तियों की सूची भी प्रस्तुत की जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन जिनके पक्ष में अंतिम आवंटन पत्र जारी नहीं किए गए हैं। इन सूचियों में आठ संसद सदस्य/उनके वार्ड, बीस विधान सभा सदस्य/उनके वार्ड, बारह न्यायिक अधिकारी/उनके वार्ड, सत्ताईस भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य/उनके वार्ड, ग्यारह भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी/उनके वार्ड, छह एचसीएस अधिकारी शामिल हैं। /उनके वार्ड, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के तीन सदस्य/उनके वार्ड, हुडा के चौदह अधिकारी/कर्मचारी/उनके वार्ड और सत्ताईस रक्षा कर्मी। इन सूचियों से यह भी पता चलता है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन में रहने वाले लगभग छह अनिवासी भारतीयों ने 14 मरला से 1 कनाल तक के भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन किया था और उन्हें वर्ष 1993 और 1996 के बीच भूखंड आवंटित किए गए थे। अन्य दस जिन अनिवासी भारतीयों ने गुड़गांव में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन किया था, उन्हें भूखंड नहीं दिए गए हैं। 10 मरला और उससे अधिक माप वाले भूखंडों के आवंटन की सूची से पता चलता है कि 1.1.1991 और 22.4.1996 के बीच विभिन्न शहरी संपदाओं में निम्नलिखित संख्या में भूखंड आवंटित किए गए हैं: -

54. हम उल्लेख कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कई शिकायतें कीं कि हुडा ने पूरी जानकारी नहीं दी है और विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन से लाभान्वित होने वाले बड़ी संख्या में व्यक्तियों के नाम छोड़ दिए गए हैं। हुडा की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि हुडा के अधिकारियों ने सूचियां तैयार करने के लिए वास्तविक प्रयास किए हैं और यदि कोई गलती हुई है तो वह अनजाने में हुई होगी। हमारी राय में, यह पक्का निष्कर्ष दर्ज करना संभव नहीं है कि हुडा द्वारा दी गई जानकारी झूठी या अधूरी है।

55. हमने जन प्रतिनिधियों, महत्वपूर्ण नागरिक पदों के धारकों, न्यायपालिका आदि के सदस्यों और उनके वार्डों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत बड़ी संख्या में आवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की है। हमने एक कनाल से दो कनाल तक के भूखंडों के आवंटन की मांग करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कुछ आवेदनों का भी अवलोकन किया है। आवेदनों और उन पर पारित आदेशों को पुन: प्रस्तुत करके इस आदेश की मात्रा को अनावश्यक रूप से बढ़ाना आवश्यक नहीं है, लेकिन साथ ही, हम इन आवेदनों की जांच से सामने आए कुछ चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर करना उचित समझते हैं। ये हैं:-

(i) लगभग सभी आवेदनों में, आवेदकों ने विवेकाधीन कोटा से किसी विशेष शहरी संपत्ति में विशेष आकार के भूखंडों के आवंटन की इच्छा व्यक्त की है, कुछ आवेदकों ने सार्वजनिक पद छोड़ने के बाद दिल्ली/चंडीगढ़ के पास बसने की इच्छा व्यक्त की है। कार्यालय या सेवा से सेवानिवृत्ति यह कहकर कि उनके रिश्तेदार दिल्ली के पास रहते हैं। कुछ मामलों में आवेदकों ने कहा है कि वे आतंकवाद से पीड़ित हैं।

(ii) किसी भी आवेदन की जांच 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद' के मानदंड के संदर्भ में नहीं की गई थी। प्रतिवादी नंबर 3 और उसके अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने यह दर्ज नहीं किया कि आवेदक ने जीवन के एक विशेष क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है और वह जरूरतमंद है। सभी मामलों में, प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/उप. मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/निजी सहायक ने आदेश इस प्रकार दर्ज किया:-

"सीएम की इच्छा है कि सेक्टर...(शहरी संपत्ति का नाम) में प्लॉट नंबर...यदि उपलब्ध हो और सीएम के डीक्यू के तहत आवंटन योग्य हो तो आवेदक को आवंटित किया जा सकता है।"

(iii) सभी मामलों में हुडा के अधिकारियों ने औपचारिक आवंटन पत्र जारी करने से पहले आवेदक का शपथ पत्र और प्रीमियम राशि ले ली। हुडा के अधिकारियों ने भी अपनी ओर से ऐसे लोगों से प्लॉट आवंटित करने की पात्रता के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। किसी भी मामले में, हुडा अधिकारियों ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को किसी अन्य शहरी संपत्ति में विवेकाधीन कोटा के तहत प्लॉट आवंटित किया गया है या आवंटी या आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को 'घर' मिला है संबंधित शहरी संपत्ति या चंडीगढ़ या मोहाली।

(iv) कई संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य जो हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों, अर्थात् बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, पंजाब से चुने गए; केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तियों/उनके वार्डों को विवेकाधीन कोटा के तहत फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला की शहरी संपदा में भूखंड आवंटित किए गए हैं। हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों की अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को बड़ी संख्या में विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए गए हैं। उनमें से कुछ हैं श्री जगदीप धनखड़, पूर्व सांसद (राजस्थान); श्री मणिशंकर अय्यर (तमिलनाडु); श्री वीरेंद्र कटारिया (पंजाब); श्रीमती ओमेन मेयोंग (अरुणाचल प्रदेश); श्री एनके सेल्वी; श्री अरविंद नेताम; श्री पीए संगमा; श्री एसएस कैरों; श्री जी. वेंकटस्वामी; श्री पी.वसुंधरा; श्री विश्वजीत पी. सिंह; श्री बूटा सिंह; श्रीमती विमला शर्मा और श्री आशुतोष दयाल शर्मा; श्री एस.सी. जमीर (मुख्यमंत्री-नागालैंड); श्री कोइंद सिंह (विधायक - राजस्थान); श्री अरुण शर्मा (शिमला); कुमारी ज्योति, विधायक (पटना) श्री एसएस बरनाला (पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब); श्री सुनील अरोड़ा (राजस्थान से आईएएस अधिकारी); सुश्री लीना नायर (तमिलनाडु से आईएएस अधिकारी); श्री जीएल भगत (अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट); श्री वीके जैन (संयुक्त सचिव, केंद्र सरकार); श्री एस.के. भटनागर (रक्षा सचिव, भारत सरकार); श्री तेजिंदर खन्ना (आईएएस अधिकारी, पंजाब कैडर), श्री वीके दुग्गल (आईएएस अधिकारी, यूटी कैडर); श्री आर.के. आहूजा; निफ़िस इब्राहिम; नीलमाधब मोहंती; डीएस बग्गा; कुमारी नीता चौधरी (यूपी); डॉ. एम. जफर आलम (अध्यक्ष, पश्चिम रेलवे भर्ती बोर्ड); श्री अनिल कुमार (राजस्थान); श्री अशोक भटनागज (अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड); श्री जे.एस. भूरिया (बिहार); श्री के. शमशेर सिंह (एचपी कैडर; श्री आरआर भारद्वाज (पंजाब) और श्री केएस सिद्धू (महाराष्ट्र)।

(v) सांसद श्री इंद्रजीत की दो बेटियों, सुश्री सैबिना और सुश्री सोनिया ने भूखंडों के आवंटन के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को 18.9.1993 को आवेदन किया था। इन दोनों आवेदनों पर, प्रतिवादी नंबर 2 ने 31.10.1993 और 10.11.1993 को समान आदेश पारित कर सेक्टर 10-ए, गुड़गांव में प्लॉट नंबर 1259 और 1170 के आवंटन का निर्देश दिया।

(vi) श्री राम सिंह चौधरी, श्री बी. दिवाकर, श्री संजीव जिंदल, श्री ए.डी. गौड़ और सुश्री रितु गर्ग जैसे न्यायिक अधिकारियों, जिन्होंने कुछ वर्षों तक सेवा प्रदान की है, ने आवेदन किया और अपने नाम पर भूखंड आवंटित कर लिए। हरियाणा के सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीके कौशल की पत्नी और बेटे को दो प्लॉट मिले, जबकि हमें बताया गया कि श्री कौशल के पास पंचकुला में एक घर है। स्वर्गीय श्री न्यायमूर्ति एसडी बजाज ने 19.12.1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हुकम सिंह को एक भूखंड आवंटन के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन पर मुख्यमंत्री ने प्लॉट नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया. 1608 सेक्टर 15(II) गुड़गांव में एक कनाल माप। यह श्री बजाज की इच्छा के अनुरूप ही था। श्रीमती स्वर्गीय श्री एसडी बजाज की पत्नी उर्मिला बजाज ने विवेकाधीन कोटे के तहत शहरी संपत्ति, पानीपत में प्लॉट के आवंटन के लिए दिनांक शून्य दिनांक के साथ एक आवेदन किया और मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव ने प्लॉट संख्या के आवंटन के लिए दिनांक 6 दिसंबर, 1994 को आदेश पारित किया। 1258(9) सेक्टर 13/17, पानीपत में। इसी प्रकार श्रीमती सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस दीवान की पत्नी प्रोमिला दीवान ने जनवरी, 1992 में एक कनाल के भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया था और शहरी संपत्ति, करनाल में भूखंड के आवंटन के लिए निर्देश 10.1.1992 को दिया गया था। श्री एसएस दीवान (सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश) की बेटी सुश्री सबीना दीवान ने भी 2.1.1992 को प्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन किया और मुख्यमंत्री ने उन्हें करनाल के सेक्टर 7 में एक कनाल का प्लॉट आवंटित करने का निर्देश दिया। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि श्री एसएस दीवान मकान नं. 642, सेक्टर 11-बी, चंडीगढ़। श्री न्यायमूर्ति हरबंस सिंह राय ने 11.1.1991 को गुड़गांव में एक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया और उन्हें सेक्टर 15(11) में एक कनाल का भूखंड मिला। उनका भी एक घर चंडीगढ़ (मकान नंबर 162, सेक्टर 9-ए) में है। श्रीमती श्री जीसी मितल (सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश) की पत्नी और बेटे शीला मितल और श्री निपुण मितल को पंचकुला और गुड़गांव की शहरी संपदा में एक-एक कनाल के भूखंड आवंटित किए गए हैं। दोनों चंडीगढ़ के मकान नंबर 7, सेक्टर 9 के निवासी हैं। इस न्यायालय के एक या दो मौजूदा न्यायाधीशों ने भी विवेकाधीन कोटा के तहत अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूखंड आवंटित किए हैं।

(vii) श्री एचएल सिब्बल, श्री कपिल सिब्बल और श्री वीके जैन आदि सहित कुछ प्रतिष्ठित वकीलों को भी विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड मिले।

(viii) कई मामलों में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भूखंड आवंटित किए गए हैं। उनमें से कुछ हैं सुश्री रेनू बिश्नोई और सुश्री नीटू बिश्नोई बेटियाँ और श्री दुरा राम के पुत्र श्री संदीप बिश्नोई; श्री आशुतोष मोहंता और श्रीमती। श्री एससी मोहंता के पुत्र और पत्नी बंसी देवी; श्री बीएस ओझा और उनके पुत्र संदीप ओझा; श्री लीला किशोर के पुत्र श्री भूपिंदर कुमार और श्री तरूण चौधरी; अनिल बाली और सुनीता बाली श्री छब्बन लाल के पुत्र और पुत्री; श्री वाईएन दीदी के पुत्र संजीव दीदी और राजीव दीदी; श्रीमती हरमोहिंदर कौर संधू और उनके बेटे मोइदीप एस. संधू; श्री के. सहगल और उनके पुत्र पंकज शगल; वरुणा भंडारी और विवेक भंडारी श्री केपी भंडारी की बेटी और बेटे; श्री एम.सी.गुप्ता और उनके पुत्र अनुराग गुप्ता; श्री हरि सिंह नलवा के पुत्र विपिन कुमार और विनय कुमार; अजमत खान (दो कथानक); श्री राम बिलास शर्मा (दो कथानक); श्री मोहम्मद इलियास (दो प्लॉट); श्री सुभाष बत्रा और उनकी पत्नी कल्पना बत्रा; श्री कृष्ण कुमार कौशल एवं विनोद कुमार कौशल; मोहिंदर पाल के बेटे सतीश कुमार और अशोक कुमार; सोहन लाल के पुत्र सूरज लाल और दुरी लाल; विनय चौधरी और उषा चौधरी, श्री ए.सी. चौधरी के पुत्र और पत्नी; श्री जीसी मित्तल की पत्नी और पुत्र शीला मितल और निपुण मितल; श्रीमती प्रोमिला दीवान और सुश्री सबीना दीवान, श्री एसएस दीवान और श्रीमती की पत्नी और बेटी। उर्मिला बजाज और स्वर्गीय श्री एसडी बजाज।

(ix) लोक सेवा आयोगों/अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों/सदस्यों के आवेदनों वाली फ़ाइल; आईएएस/आईपीएस/पीसीएस अधिकारियों और हुडा के अधिकारियों/कर्मचारियों/उनके वार्डों से पता चलता है कि प्रत्येक मामले में मुख्यमंत्री से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक स्टीरियो-प्रकार का आदेश पारित किया गया था।

(x) एक मामले में जो खुलासा हुआ वह यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री एसजेएस छतवाल ने अपने बेटे के लिए फरीदाबाद में एक भूखंड के आवंटन के लिए 29.6.1995 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि उनके पास पहले से ही एक घर है। सेक्टर 21, फ़रीदाबाद में। उस आवेदन पर मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव ने दिनांक 29.9.1995 को श्री छतवाल के पुत्र के नाम पर सेक्टर 46, फ़रीदाबाद में एक भूखंड आवंटित करने का आदेश पारित किया।

(xi) पूर्व प्रधानमंत्रियों के अधिकारियों और उनके आवासों पर बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं; हरियाणा भवन, नई दिल्ली और हरियाणा निवास, चंडीगढ़ के कर्मचारियों को 2 से 6 मार्ले के भूखंड आवंटित किए गए हैं।

(xii) सैकड़ों आवंटी प्रतिवादी संख्या 2 के अकेले जिले से हैं। उन्हें 6 मरला से 2 कनाल तक के भूखंड आवंटित किए गए हैं।

(xiii) दलीलों के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जिस आवंटन पर प्रकाश डाला, वह श्री सुरेंद्र सिंह कैरों, पूर्व सांसद से संबंधित है। श्री प्रताप सिंह कैरों (पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब) के पुत्र। उनके पास चंडीगढ़ में एक आलीशान घर है और उन्हें

पंजाब राज्य में सिनेमा हॉल और फार्म हाउस जैसी बड़ी संपत्ति मिली है। उन्होंने इस आधार पर एक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया था कि उनकी संपत्ति 1994 के दंगों के दौरान नष्ट हो गई थी। प्रतिवादी नंबर 2 के निर्देश के तहत, एक प्रतिष्ठित और जरूरतमंद के रूप में उनके दावे की जांच किए बिना विवेकाधीन कोटा के तहत उन्हें आवंटन किया गया था। व्यक्ति।

(xiv) प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुश्री माधुरी दीक्षित को वर्ष 1996 में उनकी चंडीगढ़ यात्रा के दौरान एक प्लॉट आवंटित किया गया था। अपने आवेदन में, सुश्री दीक्षित ने बस अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वह पंचकुला में बसना चाहती थीं और प्रतिवादी नंबर 3 ने तुरंत सहमति दे दी। उसे एक कनाल का प्लॉट आवंटित करके। इसी प्रकार, एक अन्य फिल्म अभिनेत्री सुश्री प्रीति सप्रू ने आवेदन किया और उन्हें अर्बन एस्टेट पंचकुला में एक प्लॉट आवंटित किया गया। इन दोनों अभिनेत्रियों ने अपने आवेदन में अपना पता बॉम्बे का बताया है.

56. उपर्युक्त तथ्यों से पता चलता है कि 10 मरला से 2 कनाल तक के भूखंडों का आवंटन महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तियों, सिविल सेवकों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित न्यायपालिका के सदस्यों के पक्ष में किया गया है। कुछ मामलों में इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के परिवारों के सदस्यों और रिश्तेदारों को आवंटन किया गया है। प्रमुख शहरी संपदा में बड़े भूखंडों के आवंटन से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने उन लोगों को लाभ पहुंचाया जो उच्च सार्वजनिक पदों पर बैठे थे और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम थे। जिस आकस्मिक तरीके से प्रतिवादी नंबर 3 के आदेश पर आदेश पारित किए गए, उससे पता चलता है कि हुडा द्वारा किसानों और अन्य लोगों से अर्जित सार्वजनिक संपत्ति को माननीय मुख्यमंत्री की निजी संपत्ति माना गया था। इन आवंटनों ने जनता के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है कि जो लोग शक्तिशाली और अमीर हैं वे राज्य तंत्र का उपयोग अपने लाभ के लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकते हैं। यह भावना कि भविष्य में लाभ कमाने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे आवंटन सुरक्षित कर लिए गए हैं, पूरी तरह से निराधार नहीं माना जा सकता है। कुछ आवंटी चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य स्थानों पर आलीशान घरों में रह रहे हैं। अन्य लोग राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड, गुजरात आदि राज्यों में रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश ने भूखंडों के आवंटन के 4 से 5 साल की समाप्ति के बाद भी घर नहीं बनाया है। फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला की शहरी संपदा में भूखंडों की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। इन शहरी संपदाओं की दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से निकटता एक प्रमुख कारक है जिसने इन स्थानों पर जमीन की कीमतों में कई गुना वृद्धि में योगदान दिया है। एक प्लॉट जो वर्ष 1991 में विवेकाधीन कोटा के तहत रुपये की कीमत पर आवंटित किया गया होगा। एक लाख और जो बाजार में रुपये की दर से खरीदा जा सकता था। वर्ष 1991 में दो लाख, अब रुपये की कीमत मिलेगी। दस लाख या उससे अधिक. इसलिए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि विवेकाधीन कोटा का उपयोग प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा सार्वजनिक हित की कीमत पर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। वास्तव में, यदि पिछले दस वर्षों के दौरान विवेकाधीन कोटा के तहत 8000 से अधिक भूखंड आवंटित नहीं किए गए होते, तो यह उन लोगों को उपलब्ध कराया जाता, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

57. प्रतिवादी नंबर 3 शायद यह कहकर सार्वजनिक संपत्ति के वितरण में निष्पक्ष और न्यायसंगत होने का श्रेय ले सकता है कि उसने देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लोगों को उपकृत किया है। वह यह भी कह सकता है कि राज्य के तीनों अंगों, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्यों के साथ उसके द्वारा समानता का व्यवहार किया गया है क्योंकि विवेकाधीन कोटा के तहत आवंटन के लाभार्थियों में संसद सदस्य शामिल हैं; विधान सभाओं के सदस्य; कार्यपालिका के शीर्ष पद जैसे मुख्य सचिव और सबसे निचले पायदान यानी चपरासी आदि और न्यायपालिका के सदस्य। यहां तक कि वर्दीधारी और विदेश में रहने वाले लोग भी ऐसे आवंटन से लाभान्वित हुए हैं। हालाँकि, हमें अनुच्छेद 14, जो कि संविधान की मूल संरचनाओं में से एक है, में सन्निहित समानता के सिद्धांत की ऐसी विकृत व्याख्या को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता है। प्रतिवादी नंबर 3 की कार्रवाई भले ही बीते दिनों की देहाती सादगी के अनुरूप रही हो, लेकिन यह इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ पूरी तरह से असंगत है। बल्कि उन लोगों को भूखंडों का आवंटन, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से या जिनके परिवार के पास पहले से ही दिल्ली और चंडीगढ़ सहित अन्य स्थानों पर घर हैं, याचिकाकर्ता की दलील को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि ऐसे आवंटन का उपयोग धन के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा।

58. इन आवंटनों का एक और परेशान करने वाला पहलू यह है कि न्यायपालिका के सदस्य और लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसी एजेंसियां, जिनसे संपत्ति अधिग्रहण के आकर्षण से दूर रहने की उम्मीद की जाती है, दुर्भाग्य से भूमि के आकर्षण का शिकार हो गए हैं। . न्यायपालिका और लोक सेवा आयोगों और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसी एजेंसियों के सदस्यों को भूखंडों के आवंटन के लिए विवेकाधीन कोटा के उपयोग से इन संस्थानों की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान होने की संभावना है।

59. उत्तरदाताओं और आपत्तिकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील की अन्य दलीलें।

(1) प्रतिवादी नंबर 3 के विद्वान वकील श्री एचएल सिब्बल ने अशोक कुमार बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करके निर्वाचित प्रतिनिधियों, न्यायपालिका के सदस्यों और नौकरशाहों को किए गए आवंटन को बरकरार रखने के लिए हमें

मनाने के लिए गंभीर प्रयास किए। मारुति उद्योग लिमिटेड, एआईआर 1986 एससी 1923। हमने उस निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, लेकिन, हमारी राय में, इसे कानून के किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, उनके आधिपत्य ने निर्माता के 5% कोटा में से मारुति वाहनों के आवंटन के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी। उस निर्णय को इस प्रस्ताव के अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण जो सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, वह अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों को उदारता और अनुग्रह वितरित कर सकता है। हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के लिए जो बाध्यकारी है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा है और इसलिए, अशोक कुमार के मामले में पारित आदेश पर सार्वजनिक अधिकारियों की पूरी तरह से मनमानी और मनमौजी कार्रवाइयों को बरकरार रखने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो इसे हिला देते हैं। लोकतांत्रिक संस्था की नींव और जो बुनियादी संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हैं।

(2) आवंटनों को रद्द करना संभावित होना चाहिए।

श्री एमएल सरीन ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवेकाधीन कोटा अधिनियम या संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, तो प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा किए गए आवंटन में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए और सिद्धांतों को निर्धारित किया जाना चाहिए हमारे द्वारा नीचे को भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने एसआर दास के मामले (सुप्रा), प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद बनाम बी. करुणाकर, जेटी 1993 (1) एससीएल और न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के मोशन बनाम प्रशासक के सलाहकार पर की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया। , यूटी, चंडीगढ़ , 1995(2) पीएलआर 451। हमारी राय में, श्री सरीन के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को केवल शीर्ष न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य , एआईआर 1967 एससी 1643 में लागू किया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें संविधान (17वां संशोधन) अधिनियम द्वारा किए गए कुछ संशोधनों की संवैधानिक वैधता थी । 1964 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। संवैधानिक संशोधनों की वैधता का समर्थन करते हुए, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत का आह्वान किया, जिसे अमेरिका में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। उनके आधिपत्य ने माना कि इस सिद्धांत को केवल हमारे संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में ही लागू किया जा सकता है और इसे केवल शीर्ष न्यायालय (निर्णय के पैरा 15) द्वारा ही लागू किया जा सकता है)। करुपाकर के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों की व्याख्या की, जैसा कि वे संविधान (42वें संशोधन) अधिनियम , 1976 द्वारा उनके संशोधन के बाद मौजूद हैं। उनके आधिपत्य ने दो स्पष्ट रूप से विरोधाभासी निर्णयों को नोटिस किया और बरकरार रखा। भारत संघ बनाम मोहम्मद रमज़ान खान, जेटी 1994(4) एससी 456 में व्यक्त विचार । हालाँकि, संविधान पीठ ने आगे कहा कि मोहम्मद रमज़ान खान मामले में निर्धारित कानून को संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि उस कानून को आदेशों पर लागू किया जाना चाहिए। जो पहले ही अंतिम हो चुका था, असंख्य जटिलताएँ पैदा करेगा और प्रशासन पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यापक जनहित की मांग है कि मोहम्मद रमजान खान के मामले में फैसले से पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराए बिना पारित सजा के आदेशों में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम प्रशासक यूटी, चंडीगढ़ के सलाहकार पर(सुप्रा), इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने सरकारी आवास (चंडीगढ़) प्रशासन पूल) आवंटन नियम, 1972 की वैधता की जांच की और उसके नियम 7 को रद्द कर दिया। न्यायालय ने श्री एआर तलवार को किये गये आवंटन को भी रद्द कर दिया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि आवंटियों द्वारा उप-किराए पर दिए गए सरकारी आवासों की वसूली की जानी चाहिए। हमारी राय में, न तो करुणाकर का मामला और न ही न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम प्रशासक के सलाहकार पर निर्णय..... को एक प्रस्ताव देने के रूप में पढ़ा जा सकता है कि न्यायालय को सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो स्पष्टतः संविधान और जनहित के विरुद्ध हैं। वास्तव में, करुणाकर के मामले में मोहम्मद रमज़ान खान के मामले में घोषित कानून को संभावित रूप से लागू करने का निर्देश व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। पूर्ण पीठ द्वारा निर्णयित दूसरे मामले में, सिद्धांतों को केवल भविष्य में लागू करने का कोई निर्देश नहीं है। केवल कुछ मुद्दों के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि जिन लोगों के पास नियम 12 के अनुसार मकानों का कब्जा था, उन्हें उसके द्वारा दर्ज निष्कर्षों के आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उस मामले का वर्तमान मामले से कोई लेना-देना नहीं है जिसमें हमने उच्च सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित शक्ति का बेतहाशा दुरुपयोग पाया है। इसलिए, हमें यह मानने का कोई आधार नहीं मिलता कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा विवेकाधीन कोटा के तहत किए गए आवंटन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

(3) नोटिस से तीन साल पहले किए गए आवंटन में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। आपत्तिकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री सरीन और विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जो आवंटन न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने से तीन साल पहले किए गए हैं, उनमें गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए और सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि लागू की जानी चाहिए । तत्काल मामले में. श्री सरीन ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया:-

(i) पंजाब राज्य बनाम गुरदेव सिंह , एआईआर 1991 एससी 2219 और

(ii) केरल राज्य बनाम एमकेएचएम मणिकोथ नाडुविल (डीड) और अन्य, 1995(8) एससी 533।

श्री सरीन एवं अन्य विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है। केरल राज्य बनाम एमकेएचएम मणिकोथ (सुप्रा) मामले में, शीर्ष न्यायालय केरल भूमि सुधार अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण से निपट रहा था। केरल उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द कर दी। उच्च न्यायालय के आदेश को उलटते हुए, उनके आधिपत्य ने 'शून्य' शब्द की व्याख्या की और माना कि पार्टियों के बीच दिए गए एक शून्य आदेश या निर्णय को भी सभी मामलों और सभी स्थितियों में अस्तित्वहीन नहीं कहा जा सकता है। पंजाब राज्य बनाम गुरदेव सिंह (सुप्रा) में, उनके आधिपत्य ने घोषणा की कि बर्खास्तगी गलत तरीके से सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 के तहत कवर की गई है और यदि कोई कर्मचारी सीमा की अवधि के भीतर बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती नहीं देता है, तो मुकदमा दायर किया जाएगा। सिविल न्यायालय संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए दायर मुकदमे में आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन दो मामलों में निर्धारित सिद्धांत का इस याचिका में उठाए गए मुद्दे पर कोई असर नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग से संबंधित है, जिन्हें सार्वजनिक विश्वास और जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। दिलचस्पी। एक बार जब हमने पाया कि अधिनियम के तहत, उत्तरदाताओं को पूर्ण और बेलगाम विवेक प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय संपत्ति को बहाल करने के अपने कर्तव्य में विफल हो जाएगा क्योंकि यह जनता ही है जो राज्य में निहित संपत्ति की वास्तविक मालिक है।

(4) आदेश दिनांक 29.6.1987 जारी होने की तिथि तक आवंटन किया गया। उत्तरदाताओं और आपत्तिकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जिन आवंटनों को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है या जिन्हें एसआर दास के मामले (सुप्रा) में न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस तर्क में पर्याप्त दम नजर आता है। हमारी राय में, उन आवंटनों को परेशान करना उचित नहीं होगा जिन्होंने एसआर दास के मामले में दिए गए फैसले के आलोक में वैधता का रंग हासिल कर लिया है।

(5) वास्तविक खरीदार जिन्होंने मकान और अन्य इमारतों का निर्माण किया है/मूल आवंटी जिन्होंने हुडा से अनुमति के बाद इमारतों का निर्माण किया है।

आपत्तिकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री अग्रवाल और अन्य विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि भले ही प्रतिवादी संख्या 3 और अन्य मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए आवंटन अवैध पाए जाते हैं, न्यायालय को उन मामलों में उनकी संपत्तियों के आवंटन को विघटित नहीं करना चाहिए जहां निर्माण हुडा के अधिकारियों से अनुमति लेने और योजनाओं की मंजूरी के बाद उठाया गया है। हमें विद्वान वकील के तर्कों में पर्याप्त बल मिलता है। जिन लोगों ने हुडा से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बाद निर्माण में अपना पैसा निवेश किया है, उन्हें उचित रूप से उन लोगों से अलग वर्ग के रूप में माना जा सकता है जिन्होंने अब तक निर्माण नहीं किया है। बड़ी संख्या में आवंटियों/सच्चाई खरीददारों ने अपनी जीवन भर की कमाई मकानों आदि के निर्माण में निवेश की होगी। इसलिए, यह उचित और न्यायसंगत होगा कि इस आधार पर उनके कब्जे से छेड़छाड़ न की जाए कि उनके पक्ष में किया गया आवंटन इसके विपरीत है। अधिनियम और संविधान के प्रावधान। हमारी यह भी राय है कि जिन लोगों ने हुडा की मंजूरी से मूल आवंटियों से संपत्ति खरीदी है और निर्माण कार्य बढ़ाया है, वे इस श्रेणी में आते हैं। जिनकी भवन योजना स्वीकृत हो चुकी है और जिन्होंने इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने की तारीख तक निर्माण शुरू कर दिया था, वे भी अपना कब्जा बरकरार रखने के हकदार होंगे। हालाँकि, हम हुडा को यह शर्त लगाने का निर्देश देना उचित समझते हैं कि ऐसे आवंटी/हस्तांतरणकर्ता अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए संपत्तियों को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

(5) सशस्त्र बलों के सदस्य:

कई आपत्तिकर्ता रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों के सदस्य हैं। उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से दलील दी कि उन्हें किए गए आवंटन में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान और अन्यथा देश की सेवा की है। सभी रक्षा कर्मियों को उन व्यक्तियों की श्रेणी में रखना संभव नहीं है जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है या जिन्होंने सशस्त्र बलों में विशिष्ट सेवा प्रदान की है, लेकिन हम पाते हैं कि कुछ आपत्तिकर्ताओं ने रक्षा में खुद को प्रतिष्ठित किया और सेवाएं प्रदान कीं राष्ट्र को जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ऐसे आवंटी अपने आप में एक वर्ग बना लेते हैं। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 4 को एक समिति के माध्यम से रक्षा कर्मियों को किए गए आवंटन और उन लोगों को किए गए आवंटन की जांच करने का निर्देश देना न्याय के हित में होगा जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में खुद को प्रतिष्ठित किया है। परेशान नहीं किया जा सकता.

(6) पुलिस कर्मी जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है:

यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि कई पुलिस कर्मियों ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों और देश में अन्य जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। हो सकता है कि वे/उनका परिवार सुरक्षा कारणों से उस राज्य में नहीं

रहना चाहें जहां उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे भी अपने आप में एक वर्ग का गठन करते हैं। इसलिए, यह निर्देश देना उचित होगा कि उनके मामलों की भी सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा नए सिरे से जांच की जाए और उन लोगों को किए गए आवंटन में गड़बड़ी की जाए जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में खुद को प्रतिष्ठित किया है।

(7) आतंकवाद के कारण पीड़ित नागरिक:

व्यक्तियों का एक अन्य वर्ग जो इस उपचार के पात्र हैं, वे नागरिक हैं जो पंजाब राज्य और जम्मू-कश्मीर या अन्य जगहों पर आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण पीड़ित हुए होंगे। उन्हें अपने मूल राज्य के बाहर बसने के लिए हरियाणा में प्लॉट मिल गया होगा। उत्तरदाता संख्या 1, 2 और 4 देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण पीड़ित नागरिकों को किए गए आवंटन और ऐसे व्यक्तियों के परिवारों के वास्तविक दावों को समिति को संदर्भित करेंगे कि उन्हें एक को बनाए रखने की अनुमति दी जाए। प्लॉट स्वीकार किया जा सकता है:

(8) 2 से 6 मरले तक के भूखंडों के आवंटन;

2 से 6 मरले के भूखंडों के विवेकाधीन कोटे के तहत कई आवंटन किए गए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे आवंटियों ने मुनाफाखोरी की मंशा से भूखंडों का आवंटन हासिल किया है। इसलिए, जिन लोगों को विवेकाधीन कोटे के तहत 2 से 6 मरले के प्लॉट मिले हैं, उनके आवंटन रद्द न करना न्यायसंगत होगा।

60. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि रक्षा कर्मियों की श्रेणी में, पुलिस बलों के सदस्य, आतंकवाद के कारण पीड़ित नागरिक और 2 से 6 मरला भूखंडों के आवंटियों को ऐसे भूखंडों को बनाए रखने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उनका परिवार भी शामिल हो। पति/पत्नी, बेटे और बेटियों के पास हरियाणा/चंडीगढ़ राज्य में कोई घर नहीं है और किसी भी परिस्थिति में एक परिवार को एक से अधिक प्लॉट रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

61. मामले को समाप्त करने से पहले, हम यह देखना उचित समझते हैं कि न्यायालय ने उन सभी को नोटिस जारी किया था, जिन्हें पिछले 10 वर्षों और उससे अधिक के दौरान मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे ताकि सभी को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। ऐसे व्यक्ति. हालाँकि, हमारी राय है कि जिन लोगों को आदेश दिनांक 29.6.1987 जारी होने से पहले और दिनांक 31.10.1989 के परिपत्र के माध्यम से रद्दीकरण पत्र वापस लेने से पहले भूखंड आवंटित किए गए थे, वे आवंटन रद्द करने से परेशान होने के पात्र नहीं हैं क्योंकि ऐसे अधिकांश एसआर दास के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा आवंटन को बरकरार रखा गया है। हमने अपना आदेश उन लोगों तक ही सीमित रखा है जिन्हें 31 अक्टूबर 1989 के बाद मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए गए हैं।

62. उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम मानते हैं:-

(1) अधिनियम की धारा 15 और धारा 30 के प्रावधान मुख्यमंत्री को अपने विवेक के अनुसार आवासीय भूखंडों को आवंटित करने के लिए बेलगाम और अनियंत्रित शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं और इसका उपयोग मुख्यमंत्री को ऐसी शक्तियों के प्रावधान को बनाए रखने के लिए नहीं किया जा सकता है। मंत्री;

(2) कि मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 21.11.1990 के नोट के माध्यम से भूखंडों के आवंटन के लिए तैयार किए गए मानदंड यानी 'प्रतिष्ठित और जरूरतमंद लोगों' अस्पष्ट और मनमाने हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ;

(3) 31.10.1989 को या उसके बाद मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत किए गए आवासीय भूखंडों के आवंटन को अवैध घोषित किया जाता है और रद्द किया जाता है। यह निम्नलिखित के अधीन होगा;-

(i) विवेकाधीन कोटा के तहत किए गए आवंटन बने रहेंगे और उनके वास्तविक खरीदार जिन्होंने पहले ही निर्माण कर लिया है या जिन्होंने नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले हुडा द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार घरों और भवनों का निर्माण शुरू कर दिया है। यह याचिका यानि 6.6.1996. हालाँकि, हुडा अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे आवंटियों/स्थानांतरितियों द्वारा निर्मित घरों/इमारतों को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने के लिए सामान्य निर्देश जारी करेगा।

(ii) जिन व्यक्तियों को 2 से 6 मरले के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें भी भूखंडों को बनाए रखने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब उनके परिवार के पास हरियाणा/चंडीगढ़ राज्य में कोई घर न हो। तीसरे पक्ष को अलगाव के विरुद्ध शर्त उनके मामलों में भी लागू होगी।

(iii) उन आवंटियों के मामले जो सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों के सदस्य थे/हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है या जिन्होंने सेवा के दौरान खुद को प्रतिष्ठित किया है, साथ ही पुलिस बलों के सदस्य भी हैं जो पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों और देश में अन्य जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों और देश में अन्य जगहों पर आतंकवादियों की गतिविधियों से प्रभावित हुए नागरिकों की एक समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

(iv) रक्षा कर्मियों/पुलिस अधिकारियों/पदाधिकारियों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ नागरिक जिनके मामले की समीक्षा सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा की जानी है, उन्हें सिफारिशों पर प्रति परिवार केवल एक भूखंड रखने की अनुमति दी जाएगी। समिति के. हालाँकि, वे पाँच साल तक भूखंडों को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के हकदार नहीं होंगे।

(v) आज से एक महीने के भीतर हरियाणा सरकार को सदस्यों को किए गए आवंटन के मामलों की जांच करने के लिए अधिमानतः पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। सशस्त्र बल/अर्धसैनिक बल जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है या जिन्होंने विशिष्ट सेवा प्रदान की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों और आतंकवाद के कारण पीड़ित नागरिकों के मामलों की भी जांच उस समिति द्वारा की जाएगी। सरकार और हुडा उन आवंटनों को नियमित करेंगे जिनके लिए समिति ने सिफारिशें की हैं।

(vi) यदि समिति/हुडा को पता चलता है कि किसी भी आवंटी ने हुडा को गलत जानकारी प्रस्तुत की है, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में आवंटन अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा और सरकार उचित कार्रवाई करेगी; ऐसे आवेदक पर अभियोजन.

(5) हरियाणा सरकार निर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को भूखंडों के आवंटन के लिए नीति बना सकती है और ऐसी नीति को अधिसूचित कर सकती है। ऐसी नीति के तहत आवंटन सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन सभी लोगों से आवेदन आमंत्रित करके किया जाना चाहिए जो एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं।

(6) सरकार/हुडा तुरंत पंजाब और हरियाणा राज्यों में व्यापक प्रसार वाले दो समाचार पत्रों और पूरे देश में प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन कराएगी, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि के तहत किए गए आवंटन को रद्द कर दिया गया है। विवेकाधीन कोटे से आवंटी अपने द्वारा जमा की गई धनराशि वापस पाने के हकदार हो गए हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने के दो माह के भीतर आवंटी को राशि वापस कर दी जाएगी। यदि हुडा दो के भीतर राशि वापस करने में विफल रहता है; आवेदन करने के महीनों के बाद उस पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

(7) ऊपर उल्लिखित अपवाद खंड के अंतर्गत आने वाले मामलों को संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ समिति को भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय समिति की सिफारिश पर लिया जाएगा।

(8) हुडा द्वारा किए गए आवंटनों को रद्द करने के कारण जो भूखंड उपलब्ध होंगे, उनका निपटान मौजूदा नीति के अनुसार किया जाएगा।' (9) सरकार अपने अधिकारियों और हुडा के अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

उपरोक्त तरीके से रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

एचएस बेदी, जे.

मैं उन कुछ आपत्तियों से सहमत हूं जिनका अलग से अध्ययन किया गया है।

एसएस सुधालकर, जे.

मैं जीएस सिंघवी, जे से सहमत हूं।

एचएस बेदी, जे.

भाई सिंघवी, जे. के फैसले को पढ़ने के बाद, मैं मोटे तौर पर उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं कि विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन की नीति न केवल अस्पष्ट है, बल्कि गलत भी है। इसका उपयोग अनावश्यक विचारों के लिए किया गया है और तदनुसार इसे रद्द करने की आवश्यकता है। नीचे दिए गए कारणों के लिए. मैं सिंघवी, जे से सहमत हूं कि

छोटे भूखंडों के आवंटियों को छूट दी जानी चाहिए। प्राथमिक कारक जो मुझे इस दृष्टिकोण में बाधा डालता है वह यह है कि इस नीति को एसआर दास के मामले में इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और एक डिवीजन बेंच द्वारा इसे वैध पाया गया था। दूसरे शब्दों में, वस्तुतः एक समान नीति और वर्तमान आवंटन के लिए नई चुनौती इस न्यायालय द्वारा पहले नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद दी गई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि 20 शहरी संपदाओं में 1 जून 1991 से 19 मार्च 1996 के बीच विवेकाधीन कोटा के तहत विभिन्न आकारों (नीचे विस्तृत) के कुल 4875 भूखंड (जैसा कि अनुबंध आर-19 में दिया गया है) आवंटित किए गए थे:

2 कनाल = 95

1 कनाल = 654

14 मरला = 761

10 मरला = 883

8 मरला = 262

7 मरला = 25

6 मरला = 958

4 मार्ला = 625

3 मरला = 155

2 मार्लास = 446

कुल 4875 प्लॉट

इसलिए, यह देखा जाएगा कि भूखंडों की कुल संख्या में से, 2184 भूखंड छह मरला या उससे कम के थे, इसलिए, हमारे लोगों में सबसे गरीब लोगों को आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 7 मरला और उससे अधिक के थे। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक संख्या में आवंटन गुड़गांव (1281) में किए गए हैं, उसके बाद फ़रीदाबाद (1063) और पंचकुला (754) हैं और यह स्वीकृत स्थिति है कि संभावित अपवादों को छोड़कर अन्य शहरी संपदाओं में अधिक खरीदार नहीं थे। कुरूक्षेत्र, करनाल और हिसार में क्रमशः 247, 388 और 393 भूखंड आवंटित किए गए। इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भूखंडों के लिए भीड़ मुख्य रूप से पंचकुला, फरीदाबाद और गुड़गांव में थी, क्योंकि मुनाफाखोरी शायद इन तीन शहरी संपदाओं में आवंटन मांगने का एक मकसद हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दूसरों के प्रति सम्मान के साथ आकर्षित होना। समान रूप से यह तर्क देना असंभव होगा कि जिस व्यक्ति को 2, 4 या 6 मरला का प्लॉट आवंटित किया गया था, उसने लाभ के उद्देश्य से आवंटन हासिल किया होगा। वास्तव में, प्रतिष्ठित और जरूरतमंद व्यक्तियों को आवंटन की नीति शायद ही इस श्रेणी के आवंटियों पर लागू की जा सकती है (क्योंकि किसी भी तरह से आडंबरपूर्ण या उनके प्रति अपमानजनक लगने का कोई मतलब नहीं है) उनमें से कोई भी प्रतिष्ठित और जरूरतमंद दोनों होने के योग्य नहीं होगा। जो आवंटन के लिए अनिवार्य है और इस प्रकार, उनके मामलों में कानूनी दृष्टिकोण के बजाय न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसलिए पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, आउट ऑफ टर्न सरकारी आवास आदि के आवंटन की वैधता निर्धारित करने में लागू किए गए सिद्धांतों को सिंघवी, जे. द्वारा पर्याप्त रूप से निपटाया गया है, जिन्हें वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, जहां प्लॉट खरीदे गए हैं। पॉलिसी के संदर्भ में अच्छा पैसा देने के बाद आवंटियों को, जिसे एसआर दास के मामले में पहले ही बरकरार रखा गया था। यह सर्वविदित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परिकल्पित विवेकाधीन राहत को किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए ढाला जा सकता है। इसलिए, मेरी राय है कि पिछले कई वर्षों में जो कुछ हो रहा है, उसे बनाना और उजागर करना आवश्यक है, फिर भी 2 से 6 मरला भूखंडों के संबंध में किए गए आवंटन को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

हालाँकि इस मामले का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर मेरे विद्वान भाई के साथ मतभेद है। आवंटन को रद्द करते समय, यह माना गया कि रक्षा और पुलिस कर्मियों के पक्ष में इस आधार पर एक अपवाद की आवश्यकता है कि वे एक खतरनाक राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और उनके मामले में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक सेवानिवृत्त विशिष्ट एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के रूप में उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। मुझे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं है, लेकिन मेरी राय है कि आवंटियों का एक अलग वर्ग नहीं बनाया जाना चाहिए और जिस समिति की परिकल्पना की गई है, उसे 7 मरला और उससे ऊपर के सभी भूखंडों के आवंटन की

वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे समाज के कई अन्य वर्ग चाहे वे न्यायिक अधिकारी, राजनेता, स्कूल शिक्षक या डॉक्टर हों और अन्य लोग भी राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हों और उनका मामला रक्षा कर्मियों की तरह ही वास्तविक हो सकता है। आवंटन के मानदंडों के अनुरूप। इसके अलावा समिति (इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए) में तीन सदस्य होने चाहिए - एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवक जो मुख्य सचिव के पद से कम न हो।

यह भी रिकॉर्ड में आया है कि कुछ व्यक्तियों ने झूठे हलफनामों के आधार पर और इस विषय पर नीति के विपरीत अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर दो या दो से अधिक आवंटन प्राप्त किए हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ आवंटियों ने अपने आवेदनों में गलत या गलत विवरण देकर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया है ताकि पहचान से बचा जा सके और दोहरे या एकाधिक आवंटन सुरक्षित किए जा सकें। ऐसे व्यक्तियों को एक विकल्प दिया जाना चाहिए कि यदि वे आज से दो महीने की अवधि के भीतर स्वेच्छा से एक भूखंड को छोड़कर बाकी सभी भूखंड सरेंडर कर देते हैं, तो एक भूखंड के आवंटन के लिए उनके मामलों पर उपरोक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा, और यदि वे ऐसा न करें, और जांच से पता चलता है कि यह दोहरे या एकाधिक आवंटन का मामला है, नीति के विपरीत है और झूठे शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है, तो वे न केवल खुद को आवंटन के लिए विचार किए जाने से वंचित कर देंगे, बल्कि उत्तरदायी भी बनाए जाएंगे। उस खाते पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए.

एक या दो अतिरिक्त पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री इन आवंटनों को करने और उनसे बच निकलने की स्थिति में क्यों थे, इसका एक कारण गोपनीयता और गुप्त तरीके से किया जाना था। इसलिए अब से विवेकाधीन कोटा से किए जाने वाले सभी आवंटनों को सामान्य जानकारी और सार्वजनिक जांच के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाना चाहिए।

सिंघवी, जे. ने फैसले के दौरान आवंटियों की एक सूची दी है। इसमें ऐसे कई लोग शामिल हैं जो इस देश के शासन में मायने रखते हैं या रहे हैं। हालाँकि, सूची संपूर्ण नहीं है बल्कि केवल उदाहरणात्मक है और इसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ राजनेता, सिविल सेवा अधिकारी, रक्षा कर्मी, इस उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधीनस्थ न्यायपालिका के सेवारत सदस्य शामिल हैं। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को उस नीति के तहत लाभ हुआ है जो निस्संदेह एसआर दास के मामले में जांच में खरी उतरी थी। फैसले में यह भी कहा गया है (और मैं उद्धृत कर रहा हूं) "इस न्यायालय के एक या दो मौजूदा न्यायाधीशों को भी विवेकाधीन कोटा के तहत या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूखंड आवंटित किए गए", लेकिन उनका नामकरण नहीं किया गया। मेरे विचार से और बड़े सम्मान के साथ यह चूक बेंच और फैसले को गंभीर आलोचना के लिए खुला बनाती है। आत्मनिरीक्षण एक कठिन और अक्सर शर्मनाक अभ्यास है लेकिन फिर भी यह एक ऐसा कार्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। अन्य लोगों के नामों का खुलासा करते समय, मुझे इस बात का कोई उचित कारण नहीं दिखता कि इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, यानी माननीय श्री न्यायमूर्ति एमएस लिब्रहान, माननीय श्री न्यायमूर्ति एनसी जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति एमएल कौल भी क्यों स्वयं या उनके परिवारों को लाभार्थियों में शामिल होने के रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।

रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों, जिन्होंने आवंटन प्राप्त किया है, ने सीधे मुख्यमंत्री को आवंटन के लिए आवेदन किया था और कुछ आवेदनों में ऐसी भाषा शामिल थी जो दासता की सीमा पर थी। इस प्रथा को गंभीरता से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे न्यायाधीशों की स्थिति और स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। इसलिए, मेरी राय है कि भविष्य में यदि किसी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी को विवेकाधीन कोटा के तहत भूखंड के अनुदान के लिए आवेदन करना है, तो उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए और यदि आवेदक वर्तमान न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से उच्च न्यायालय। सभी को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि किसी अन्य तरीके से किया गया कोई भी आवेदन विचार से बाहर कर दिया जाएगा।

इन आपत्तियों के साथ, मैं सिंघवी एल द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।